

[2023] 7 एस. सी. आर 670

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और ओआरएस।

वी.

रिन्यू विंड एनर्जी (राजकोट) प्राइवेट लिमिटेड

& ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 3480-3481 2020 का)

13 अप्रैल, 2023

[संजय किशन कौल, एस. रवींद्र भाट और

एम. एम. सुंदरेश, जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003-केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए मान्यता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने के नियम और शर्तें) विनियम, 2010-आर. ई. सी. विनियम 2010 के संदर्भ में विद्युत खरीद समझौता (पी. पी. ए.) दोनों पक्षों के बीच 2010 के शुल्क आदेश में निर्धारित नियंत्रण अवधि के भीतर किया गया था। राज्य आयोग ने तर्क दिया कि आर. ई. सी. विनियमों में परिवर्तन को देखते हुए पी. पी. ए. की शर्तों को बदलना पड़ा-अनुमत अपीलार्थी ने ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील दायर की, खारिज कर दी-समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी-आयोजित: ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो

राज्य आयोग द्वारा अनिवार्य पूर्व अनुमोदन, अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में पार्टियों द्वारा अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करते हुए किए गए पी. पी. ए.-राज्य आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता वाले ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष, अस्थिर-इसके अलावा, यह रिकॉर्ड की बात है कि 29.03.2012 और 10.07.2013 के बीच की अवधि के लिए और वास्तव में, दूसरे संशोधन के बाद, कोई कठिनाई नहीं थी। पीपीए के तहत पक्षों द्वारा सहमत मूल्य निर्धारण तंत्र में अनुभवी-यह 10.12.2013 पर था कि प्रतिवादी पवन ऊर्जा विकासकर्ता ने पुनर्निर्धारण के लिए राज्य आयोग से संपर्क किया

शुल्क-यह परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने का एक अवसरवादी प्रयास था, जो दूसरे संशोधन द्वारा लाया गया था, और इसे एक मौजूदा अनुबंध पर लागू करने की कोशिश की गई थी, जिसे लागू नहीं किया जा सकता है।

670 गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड।

इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. और राज्य आयोग के तर्क को बरकरार नहीं रखा जा सकता है-पी. पी. ए. द्वारा स्वेच्छा से प्रवेश किया गया

समान सौदेबाजी की शक्ति का प्रयोग करने वाले पक्ष, दूसरे से पहले

संशोधन इसकी शर्तों से प्रभावित नहीं था-विवादित आदेश में इसके विपरीत निष्कर्ष अलग रखे गए-इसके अलावा, एपीटीईएल ने सबसे अधिक घुड़सवार शैली में वस्तुतः राज्य आयोग की शर्तों पर रबर की मुहर लगा दी।

पक्षकारों द्वारा पी. पी. ए. में प्रवेश करने के संबंध में जबरदस्ती पर निष्कर्ष-अपीलार्थी के खिलाफ जबरदस्ती के आरोप के अलावा कोई सबूत या कोई अभिवचन नहीं था-संबंधित निष्कर्ष

विद्युत नियामक आयोग (से ऊर्जा की खरीद) नवीकरणीय स्रोत) विनियम, 2010-विनियम 4 (1), 9 (1)।

विद्युत अधिनियम, 2003-केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें)

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र) विनियम, 2010-चर्चा का उद्देश्य।

विद्युत अधिनियम, 2003 - एस. 64-शुल्क आदेश यू / एस. 64-आयोजित: प्रकृति में अर्ध-न्यायिक हैं और पक्षकारों पर वास्तव में बाध्यकारी हैं जब तक कि

कानून के माध्यम से संशोधित या संशोधित।

बिजली-बिजली खरीद समझौते, यदि वैधानिक अनुबंध आयोजित किए जाते हैं: बिजली खरीद समझौते अनिवार्य रूप से वैधानिक नहीं हैं।

अनुबंध से पता चलता है कि उन अनुबंधों में निहित कुछ शर्तों को कानून द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी लागू विनियम, अधिनियम के तहत-एक उत्पादक कंपनी या, जैसा कि तत्काल मामले में, एक पवन जनित्र और एक वितरण लाइसेंसधारी, जैसे कि अपीलार्थी के बीच पी. पी. ए. सावधानीपूर्वक विचार किए गए निर्णय का परिणाम है, जिसके द्वारा -

उचित विचार-विमर्श और बातचीत के बाद पक्षकार शर्तों पर सहमत होते हैं

मौजूदा कानून और विनियमों के आधार पर।

ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा लापरवाही से प्रस्तुत नहीं किए जाने वाले दबाव/दबाव/धोखाधड़ी के निष्कर्षों के आरोप-मानकों की दलीलें-आयोजित: यह है।

-

कानूनी सलाहकारों सहित, जब अनुबंधों को अंतिम रूप दिया जाता है-आकस्मिक ए. पी. टी. ई. एल. का दृष्टिकोण यह तर्क न देने में कि इस तरह के निष्कर्ष कैसे हो सकते हैं

प्रस्तुत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में, [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समान सौदेबाजी की शक्ति वाले पक्षों द्वारा किए गए अनुबंधों और सौदेबाजी के साथ, ए. पी. टी. ई. एल. से उचित अभिवचन या सबूत के बिना, या सबूत की जांच के बिना, जबरदस्ती या धोखाधड़ी के निष्कर्षों को आकस्मिक रूप से प्रस्तुत करने की उम्मीद नहीं की जाती है-बिजली अधिनियम, 2003।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. क्या वर्तमान मामले में पी. पी. ए. को राज्य आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी?

आर. डब्ल्यू. ई. और अन्य उत्तरदाताओं का आग्रह है कि पी. पी. ए. अप्रवर्तनीय था क्योंकि इसे राज्य द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

आयोग। यह तर्क निराधार और आधारहीन है। नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद से संबंधित राज्य आयोग के विनियमों (नवीकरणीय स्रोत विनियम) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था।

प्रावधान, जो राज्य आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदन को अनिवार्य करता है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में पार्टियों द्वारा अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करते हुए किए गए पी. पी. ए. वास्तव में, अक्षय ऊर्जा के मामले में, राज्य आयोग ने एक मॉडल पीपीए को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, शुल्क के नियम और शर्तें केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि राज्य द्वारा।

विनियम, 2019; दिल्ली विद्युत का विनियम 45 विनियामक आयोग आंध्र प्रदेश के व्यापक (व्यवसाय संचालन) विनियम 2001 और विनियम 36

विद्युत नियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारी)

विनियम, 2013, इस पहलू पर प्रतिवादी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष, राज्य विनियमों के प्रावधानों के तहत किसी भी निर्धारित दायित्वों पर आधारित नहीं हैं, जिसके लिए राज्य गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड v.

पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड।

कमीशन, इसके संचालन के लिए, बनाए नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 45 48] [699-एफ-जी; 700-बी-एफ]

2. क्या आर. ई. सी. विनियमों में परिवर्तन इस मामले में पी. पी. ए. के संशोधन को बाध्य करता है

अधिनियम की धारा 61 शुल्क के लिए आधार बनाती है।

दृढ़ संकल्प। दूसरी ओर, धारा 62 विभिन्न अन्य शुल्कों और शुल्कों के निर्धारण से संबंधित है। धारा 64 द्वारा शुल्क निर्धारण के तरीके और प्रक्रिया को सूचीबद्ध किया गया है आयोग। धारा 86 आयोग के कार्यों को सूचीबद्ध करती है और एक प्रमुख कार्य के रूप में शुल्क के निर्धारण को दोहराती है।

आयोग से। टैरिफ निर्धारण, निस्संदेह, विनियामक कार्य की कवायद को समझता है, जिसमें खरीद, सोर्सिंग, जनरेटर से बिजली की खरीद, वितरण और अन्य लाइसेंसधारियों द्वारा और उनकी बिक्री शामिल है। इस भाग में खरीद करने वाली संस्थाओं या लाइसेंसधारियों के साथ पी. पी. ए. (ओं) में प्रवेश करने वाली कंपनियाँ शामिल हैं। शुल्क निर्धारण एक वैधानिक कार्य है। फिर भी, धारा 42 के आधार पर, यह शक्ति की कीमत के खुली पहुंच निर्धारण के अधीन है, और धारा 63 के अधीन है जहाँ भी इसमें खुली बोली शामिल है। इस मामले के तथ्यों में, पी. पी. ए. ने उत्तरदाताओं के बीच एक शुल्क को शामिल किया और गुजरात ऊर्जा ने अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का गठन किया। आर. ई. सी. का निर्गम और बिक्री, एक

उस सौदे का महत्वपूर्ण हिस्सा, दोनों पक्षों के बीच, उनके वाणिज्यिक हित के मूल्यांकन के आधार पर। महत्वपूर्ण बात

आर. ई. सी. तंत्र की विशेषता यह है कि इसमें, डब्ल्यू. पी. डी. (यानी उत्तरदाताओं) को वितरण लाइसेंसधारियों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बिजली बेचनी पड़ती थी, जो औसत बिजली खरीद से अधिक नहीं थी।

एक्सचेंज में आर. ई. सी. के माध्यम से व्यापार किया जाने वाला घटक। द. डब्ल्यू. पी. डी. का विकल्प राज्य आयोग द्वारा निर्धारित अधिमान्य शुल्क पर लाइसेंसधारियों को बेचना था। बाद की घटना में, डब्ल्यू. पी. डी. हरित घटक के अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं थे, जो कि व्यापार योग्य आर. ई. सी. था जिसकी बिक्री से राजस्व में वृद्धि होती। प्रतिवादी डब्ल्यू. पी. डी. ने [2023] 7 एस. सी. आर. को चुना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. ई. सी. तंत्र, गुजरात ऊर्जा के साथ इन मामलों में पी. पी. ए. में प्रवेश करते हुए। डब्ल्यूपीडी द्वारा दर्ज किए गए पीपीए के लिए प्रदान किया गया पूरी अवधि (25 वर्ष) के लिए ₹ 2.64/kWh का निश्चित शुल्क, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत है (पी. पी. ए. का अनुच्छेद 5.2)। डब्ल्यूपीडी के हकदार थे और थे

बिजली विनियम में आर. ई. सी. का व्यापार, अतिरिक्त मौद्रिक लाभ प्राप्त करना: जो, प्रासंगिक अवधि में ₹1.50/kWh (पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने के समय न्यूनतम मूल्य) था। आर. ई. सी. तंत्र का विकल्प नहीं चुनने वाले डब्ल्यू पी. डी. के लिए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित तरजीही शुल्क 3.56/के. डब्ल्यू एच. था। डब्ल्यू पी. डी. किसी भी अतिरिक्त आर. ई. सी. लाभ के हकदार नहीं थे, अगर उन्होंने तरजीही शुल्क मार्ग अपनाया होता। आर. ई. सी. विनियम 2010 का विनियम 9 बिजली विनियम में आर. ई. सी. के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र निर्धारित करता है। आर. ई. सी. विनियम 2010 के विनियम 9 (1) का प्रावधान केंद्रीय आयोग को अधिकार देता है। सौर और गैर-सौर प्रमाणपत्रों के लिए न्यूनतम मूल्य और सहनशीलता मूल्य अलग से प्रदान करने के लिए केंद्रीय एजेंसी और नियामकों के मंच के साथ परामर्श। यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनहित में नियामक हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है: यदि मूल्य एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है, तो उत्तरदाताओं जैसे उत्पादकों के हितों का ध्यान रखने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाना था; यदि मूल्य बहुत अधिक हो जाता है, तो उपभोक्ताओं और वितरकों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक सहनशीलता मूल्य तय किया जा सकता है। आर. ई. सी. विनियम 2010 के विनियम 9 (2) के अनुसार, केंद्रीय आयोग को विभिन्न कारकों, जैसे (ए) विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की लागत में भिन्नता, द्वारा आधार और सहनशीलता मूल्य निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया जाना था।

सौर और गैर-सौर श्रेणी के अंतर्गत आने वाली प्रौद्योगिकियां

देश के राज्य; (बी) देश के राज्यों में खरीद की एकत्रित लागत में भिन्नता; (सी) गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अपेक्षित बिजली उत्पादन (जिसमें (i) तरजीही शुल्क के तहत अपेक्षित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (ii) प्रमाणपत्रों के तंत्र के तहत अपेक्षित नवीकरणीय ऊर्जा) (डी) विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्य शामिल हैं।

आर. ई. सी. विनियमों के विनियम 5 (1) के स्पष्टीकरण के आधार पर, "वह भारित औसत एकत्रित मूल्य जिस पर वितरण लाइसेंसधारी ने बिजली खरीदी है, जिसमें बिजली की लागत भी शामिल है।

पिछले वर्ष सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से दीर्घकालिक और अल्पकालिक स्व-उत्पादन, यदि कोई हो, लेकिन अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित स्रोतों को छोड़कर, जैसा भी मामला हो।

एक महत्वपूर्ण कारक गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड।

जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह यह है कि प्रतिवादी के सभी डब्ल्यू. पी. डी. 2010 के राज्य आयोग के शुल्क आदेश के आधार पर आर. ई. सी. विनियमों के तहत पंजीकृत थे। यह निर्विवाद है कि पंजीकरण करना आर. ई. सी. विनियम 2010 के तहत, एक इकाई (जैसे डब्ल्यू. पी. डी.) को (ए) एक राज्य एजेंसी के साथ मान्यता प्राप्त होना था [(आर. ई. सी. विनियमों के विनियम 2 (एन) द्वारा परिभाषित एक एजेंसी के रूप में "मान्यता के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करने और पंजीकरण के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए राज्य आयोग द्वारा नामित") और एक इकाई "उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिमान्य शुल्क पर बिजली बेचने के लिए इस तरह के उत्पादन से संबंधित क्षमता के लिए कोई बिजली खरीद समझौता नहीं है]। इसके अलावा, राज्य आयोग ने तरजीही शुल्क का निर्धारण करते समय अपने टैरिफ आदेश, दिनांक 30.01.2010 (जो 10.08.2009 से शुरू होने वाली नियंत्रण अवधि के साथ तीन साल के लिए चालू था) में कहा था कि यह 25 साल के लिए लागू होगा। वर्तमान मामले में, 2010 के शुल्क आदेश में निर्धारित नियंत्रण अवधि के भीतर 29.03.2102 पर पक्षों द्वारा पी. पी. ए. दर्ज किया गया था। आर. ई. सी. विनियम 2010 में परिवर्तन, जिसके लिए स्पष्टीकरण

विनियम 5 में संशोधन किया गया जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तन हुआ। पहले से मौजूद खंड कि बिजली "बिजली खरीद की एकत्रित लागत से अधिक नहीं होगी" को "बिजली खरीद की एकत्रित लागत पर" में बदल दिया गया था। यह परिवर्तन, दूसरे के माध्यम से था

(आर. ई. सी. विनियमों में) संशोधन, 10.07.2013 पर किया गया। यह रिकॉर्ड की बात है कि 29.03.2102 और 10.07.2013 के बीच की अवधि के लिए-और वास्तव में, दूसरे संशोधन के बाद, पीपीए के तहत पक्षों द्वारा सहमत मूल्य निर्धारण तंत्र में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं किया गया था। यह 10.12.2013 पर था कि प्रतिवादी WPD ने शुल्क के पुनर्निर्धारण के लिए राज्य आयोग से संपर्क किया। साफ है कि यह एक अवसरवादी प्रयास था द्वितीय संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने के लिए, और इसे एक मौजूदा अनुबंध पर लागू करने का प्रयास करें, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन कारणों से, यह है

अभिनिर्धारित किया कि ए. पी. टी. ई. एल. और राज्य आयोग का तर्क

बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। [पारस 55-59] [707-G; 708-A-H; 709-B-H; 710 A-B, E-G]

आंध्र प्रदेश पारेषण निगम लिमिटेड बनाम साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (2010) 8 एससीआर 636;

गुजरात ऊर्जा बनाम। सोलर पावर कंपनी इंडिया प्रा. लि.

[2017] 14 एस. सी. आर. 115; बेंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी।

[2023] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लिमिटेड बनाम। कोणार्क पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और अन्य। (2016) 13

एस. सी. सी. 515-संदर्भित।

3. द्वितीय संशोधन का पूर्व-विद्यमान पर लागू होना

अनुबंध-सामान्य कानून

वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. एस. में प्रवेश किया गया था

पक्षों द्वारा उचित बातचीत के बाद और मौजूदा नियमों के ढांचे के भीतर समान सौदेबाजी की शक्ति का प्रयोग: केंद्र और राज्य दोनों। इसलिए, जब तक कि कोई बाद का संशोधन स्पष्ट रूप से मौजूदा अनुबंधों को ओवरराइड नहीं करता है, तब तक इस तरह की शर्तें

समझौते पक्षों को बांधते हैं। इस प्रकार पी. पी. ए. एस. जैसे समझौते

वर्तमान मामले में, दूसरे संशोधन से पहले पक्षों द्वारा स्वेच्छा से किया गया, इसकी शर्तों से प्रभावित नहीं था। विवादित क्रम में इसके विपरीत निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है। [पारस 63,66] [714-सी; 715-जी; 716-ए]

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम सीईआरसी [2010] 3 एससीआर 609

-

प्रतिष्ठित।

पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर (पी) लिमिटेड v. असम राज्य

विद्युत बोर्ड और अन्य। [2012] 6 एससीआर 905;

आयकर आयुक्त बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड।
[2014] 12 एस. सी. आर. 1037 पर भरोसा किया।

4. क्या उत्तरदाताओं को पी. पी. ए. एस. में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था

ए. पी. टी. ई. एल., सबसे घुड़सवार शैली में, वस्तुतः रबर

पार्टियों द्वारा पी. पी. ए. में प्रवेश करने के संबंध में जबरदस्ती पर राज्य आयोग के निष्कर्षों पर मुहर लगा दी। गुजरात ऊर्जा के खिलाफ कथित जबरदस्ती के आरोप के अलावा कोई सबूत नहीं था, न ही

दलीलों की कोई विशिष्टता थी। यह समझ से परे है कि इस तरह के आरोप पर कैसे विचार किया जा सकता था और एक निष्कर्ष के रूप में शामिल किया जा सकता था, यह देखते हुए कि उत्तरदाता स्थापित कंपनियां हैं, जो बातचीत में प्रवेश करती हैं और अनुबंधों को अंतिम रूप देने पर कानूनी सलाहकारों सहित विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त करती हैं। इसलिए, जबरदस्ती के बारे में निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय हैं। ए. पी. टी. ई. एल. का अनौपचारिक दृष्टिकोण, यह तर्क न देते हुए कि इस तरह के निष्कर्षों को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में, अनुबंधों और सौदेबाजी से निपटने के लिए, जो समान सौदेबाजी की शक्ति वाले पक्षों द्वारा किए जाते हैं, ए. पी. टी. ई. एल. से उम्मीद नहीं की जाती है कि वह आकस्मिक रूप से गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड v.

रिन्यू विन एनर्जी (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड।

जबरदस्ती या धोखाधड़ी के निष्कर्ष, बिना उचित अभिवचन या पीआर या सबूत की जांच के बिना।
इसलिए जबरदस्ती के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 71] [717-एफ-जी; 718-ए-बी]

शांति बुधिया वेस्ता पटेल और अन्य। वी. निर्मला

जयप्रकाश तिवारी और अन्य। [2010] 4 एससीआर 958;

न्यू इंडियन एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीन शक्ति
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड [2014] 12 एस. सी. आर. 360 पर निर्भर था।

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। ईएमसीओ लिमिटेड

[2016] 1 एस. सी. आर. 857; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

वी. एसीएमई सोलर टेक्नोलॉजीज (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

[2017] 16 एस. सी. सी. 498; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम हार्टफोर्ड

अग्नि बीमा कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1288; उनकी

महारानी शांतिदेवी पी गायकवाड़ बनाम। सावजीबाई

हरिबाई पटेल और अन्य 2001 (5) एस. सी. सी. 101: [2001] 2 एससीआर

590 ; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। राजस्थान बिजली

नियामक आयोग [2015] 7 एस. सी. आर. 1104; गुजरात

ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। तारिणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

[2016] 5 एस. सी. आर. 990; भारत संघ बनाम इंडसइंड बैंक

लिमिटेड [2016] 11 एससीआर 700; केरल राज्य विद्युत बोर्ड

& एन. आर. वी. प्राचार्य सर सैयद तकनीकी संस्थान

अध्ययन [2020] 7 एससीआर 885; गुजरात ऊर्जा विकास निगम

सीमित वी। सोलर सेमी-कंडक्टर पावर लिमिटेड

कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [2017] 14 एससीआर 115 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2020] 7 एससीआर 885

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2017] 14 एससीआर 115

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

[2010] 8 एससीआर 636

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2016] 1 एससीआर 857

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[2017] 16 एससीसी 498

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2001] 2 एससीआर 590

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2010] 3 एससीआर 609

प्रतिष्ठित

पैरा 33

[2015] 7 एससीआर 1104

पैरा 41

[2017] 14

[2016] 5

(2016) 13

[2012] 6

[2014] 12

[2016] 11

[2010] 4

[1951] 1

[2014] 12

3481

2015

,

,

1.

1 3480

2

3 समीक्षा याचिका सं. 03/2019 गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

गुजरात विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद "राज्य आयोग") के दिनांक 01.07.20154 के आदेश की पुष्टि की गई थी।

2. प्रथम अपीलार्थी-गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

(इसके बाद "गुजरात ऊर्जा") ने समीक्षा/सुधार की मांग करने के लिए ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश को चुनौती देते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे इस अदालत ने निपटाया था। गुजरात ऊर्जा ने तब एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे ए. पी. टी. ई. एल. ने दूसरे विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। जब यह अपील सुनवाई के लिए ली गई, तो 14.10.2020 , इस अदालत ने नोटिस जारी किया था और एपीटीईएल के विवादित आदेश पर रोक लगा दी थी।

पृष्ठभूमि

3. गुजरात ऊर्जा ने वितरण की ओर से थोक में बिजली खरीदी

गुजरात राज्य में लाइसेंसधारी; यह अधिनियम के तहत शब्द के अर्थ के भीतर एक अधिकृत लाइसेंसधारी है। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें अपीलार्थी गुजरात राज्य में वितरण लाइसेंसधारी हैं। पहला उत्तरदाता, रिन्यू विंड एनर्जी (राजकोट) प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "आरडब्ल्यूई") एक पवन जनित्र है जिसने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित अक्षय ऊर्जा प्रमाणन योजना के तहत गुजरात के राजकोट जिले में 25.2 मेगावाट के पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किए थे।

(इसके बाद, "केंद्रीय आयोग")। दूसरा उत्तरदाता पवन स्वतंत्र बिजली उत्पादक संघ (इसके बाद "संघ") है। प्रतिवादी संख्या 3, गुजरात विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद "राज्य आयोग") गुजरात राज्य के लिए अधिनियम के तहत नियामक आयोग है। चौथा उत्तरदाता, विश विंड इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी (इसके बाद "विश विंड") एक पवन जनरेटर है।

4. अधिनियम की धारा 86 के अनुसार, राज्य आयोग कई कार्यों का निर्वहन करते हैं-जिसमें उत्पादन के लिए शुल्क का निर्धारण शामिल है।

4 याचिका संख्या 1363/2013 में

5 सिविल अपील सं. 15.02.2019 6 दिनांकित आदेश द्वारा धारा 86 का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है: " 86. राज्य आयोग के कार्य। - (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

(क) राज्य के भीतर, जैसा भी मामला हो, थोक, थोक या खुदरा बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और पहियों के लिए शुल्क निर्धारित करना: (ख) राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति

के लिए बिजली की खरीद के लिए समझौतों के माध्यम से उत्पादक कंपनियों या लाइसेंसधारियों या अन्य स्रोतों से बिजली की खरीद की जाने वाली कीमत सहित वितरण लाइसेंसधारियों की बिजली खरीद और खरीद प्रक्रिया को विनियमित करना; [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली की आपूर्ति, संचरण और पहियों, थोक, थोक या

खुदरा, जैसा भी मामला हो, राज्य के भीतर "। शुल्क निर्धारण

प्रक्रिया अधिनियम की धारा 62 और 64 के अनुरूप होनी चाहिए। धारा 62,

"उपयुक्त आयोग" की आवश्यकता है (इस मामले में, राज्य आयोग) के प्रावधानों के अनुसार शुल्क निर्धारित करने के लिए

अधिनियम-अन्य उद्देश्यों के अलावा, बिजली की खुदरा आपूर्ति। द.

राज्य आयोगों को भी नियम बनाने का अधिकार है, जिसके तहत

अधिनियम की धारा 181। उस शक्ति में शर्तों का निर्माण शामिल है। और धारा के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए शर्तें

61 "। इसके अतिरिक्त, शुल्क आदेश को संशोधित या लागू किया जा सकता है

धारा 64 (3) के तहत शर्तें। राज्य आयोग द्वारा निर्देशित है

अधिनियम की धारा 61 में निर्दिष्ट सिद्धांत

शुल्क नियम। इस अदालत ने माना है कि विशेषज्ञ निकायों के रूप में राज्य आयोगों को विभिन्न प्रतिस्पर्धी चिंताओं के बीच संतुलन बनाना होगा।

और ऐसे विनियमों को तैयार करते समय हित। 8 गुजरात राज्य

कमीशन, एक बहु-वर्षीय अवधि के लिए (जिसे "नियंत्रण अवधि" भी कहा जाता है),

शुल्क के निर्धारण के लिए विनियम बनाएँ। राज्य आयोग

फिर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बहु-वर्षीय शुल्क आदेश निर्धारित किया जाता है।

इसके अलावा, धारा 64 (6) में निर्धारित किया गया है कि शुल्क आदेश जारी रहेंगे। टैरिफ में निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए लागू होना

आदेश जब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है "। यदि कोई पक्ष किसी से व्यथित है

(ग) राज्य के भीतर बिजली के पारेषण और पहियों की सुविधा प्रदान करना;

(ड) किसी भी व्यक्ति को ग्रिड के साथ संपर्क और बिजली की बिक्री के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना और ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत भी निर्दिष्ट करना।

..... [.....] "

1 अधिनियम का खंड 181 (2) (जेडडी)।

8 केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. बनाम प्राचार्य सर सैयद तकनीकी अध्ययन संस्थान, 2020 7 एस. सी. आर. 885:

7. [.....] " शुल्क तय करते समय आयोग बिजली के किसी भी उपभोक्ता को अनुचित प्राथमिकता नहीं दे सकता है। हालाँकि, आयोग के पास उपभोक्ताओं के भार कारक, बिजली कारक, वोल्टेज, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत के अनुसार अंतर दरें निर्धारित करने की शक्ति है, जिस पर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जहाँ तक इन दोनों श्रेणियों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग-अलग दरें तय करने की बात है, ये कारक काम में नहीं आए। अन्य अनुमेय विभेदक कारक हैं किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और वह उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जहाँ तक विभिन्न कारकों के इस समूह का संबंध है, सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क लाभ भौगोलिक स्थिति या आपूर्ति की प्रकृति पर आधारित प्रतीत नहीं होता है। आयोग ने हालाँकि उस उद्देश्य के आधार पर शुल्क के उपरोक्त दो सेटों के वर्गीकरण को उचित ठहराया है जिसके लिए उपभोक्ताओं को आपूर्ति की आवश्यकता होती है।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

किसी दिए गए शुल्क आदेश की शर्तों के अनुसार, यह अपने संशोधन या निरसन की मांग कर सकता है। ए. पी. टी. ई. एल. को धारा 111 के तहत और उसके बाद अधिनियम की धारा 125 के तहत इस अदालत में भी आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है। अधिनियम की धारा 64 के तहत शुल्क आदेश अर्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं और जब तक कानून के माध्यम से संशोधित या संशोधित नहीं किए जाते हैं, तब तक पक्षकारों के लिए बाध्यकारी हैं। 5. 29.01.2010 पर, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा की मान्यता और जारी करने के लिए नियम और शर्तें)

अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा प्रमाणपत्र) विनियम, 2010 (इसके बाद "आर. ई. सी. विनियम 2010") केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए थे।

व्यापार योग्य और बिक्री योग्य ऋण जारी करके गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए बिजली बाजार के विकास के लिए आयोग

प्रमाणपत्र (इसके बाद आर. ई. सी.)। उक्त आर. ई. सी. का विनियम 5

विनियम 2010 आरई प्रमाणपत्रों में भाग लेने के लिए अक्षय उत्पादकों के लिए आवश्यक पात्रता प्रदान करता है:

" 5. प्रमाणपत्रों के लिए पात्रता और पंजीकरण:

(1) अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में लगी एक उत्पादक कंपनी प्रमाण पत्र जारी करने और उसमें काम करने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने की पात्र होगी यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

ए। इसने राज्य एजेंसी से मान्यता प्राप्त की है;

बी। इसके लिए कोई बिजली खरीद समझौता नहीं है

उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिमान्य शुल्क पर बिजली बेचने के लिए ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता;

और

सी। यह उत्पादित बिजली को भी बेचता है।
(i) उस क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसमें पात्र इकाई स्थित है, की एकत्रित लागत से अधिक कीमत पर

ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की बिजली खरीद, या

((ii) किसी अन्य लाइसेंसधारी को या पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर या बाजार में बिजली विनिमय के माध्यम से एक खुली पहुंच वाले उपभोक्ता को।

निर्धारित कीमत।

स्पष्टीकरण। - इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'खरीद की एकत्रित लागत' का अर्थ है भारत औसत एकत्रित मूल्य।

जिस पर वितरण लाइसेंसधारी ने पिछले वर्ष [2023] में स्व-उत्पादन की लागत, यदि कोई हो, सहित बिजली खरीदी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से दीर्घकालिक और अल्पकालिक, लेकिन अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित लोगों को छोड़कर,

मामला हो सकता है "।

6. आर. ई. सी. विनियम 2010 का उद्देश्य आर. ई. सी. जारी करने के लिए भौतिक विद्युत घटक और ऊर्जा के पर्यावरणीय (नवीकरणीय) घटक को अलग करना था। यह एक वैकल्पिक था

अक्षय ऊर्जा के प्रचार लाभ वाले प्रमाण पत्र जबकि भौतिक विद्युत घटक को किसी अन्य पारंपरिक बिजली के रूप में बेचा जाता था। आर. ई. सी. विनियम 2010 ने यह भी प्रदान किया कि आर. ई. सी. तंत्र पर आधारित जनरेटरों के पास भौतिक ऊर्जा को बेचने का विकल्प था। वितरण अनुज्ञप्तिधारी की "औसत पूंछ बिजली खरीद लागत से अधिक कीमत" (इसके बाद "एपीपीसी" के रूप में) पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि आर. ई. सी. बेचकर और उच्च प्रचार शुल्क पर भौतिक ऊर्जा बेचकर या संबंधित वितरण लाइसेंसधारी से रियायती लाभ लेकर उत्पादकों को दोगुना लाभ न हो।

7. आर. ई. सी. विनियम 2010 के तहत, वितरण लाइसेंसधारक बिजली के भौतिक घटक को खरीदने के लिए बाध्य नहीं थे।

आर. ई. सी. तंत्र के तहत स्थापित अक्षय ऊर्जा उत्पादक

ऐसे आर. ई. सी. आधारित जनरेटरों के पास बिजली के भौतिक घटक के संबंध में वैकल्पिक विकल्प थे, अर्थात् (i) बिजली विनियम की बिक्री (ii) पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए बिजली का चक्र या (iii) अपनी खपत के लिए बिजली का चक्र। बिजली के भौतिक घटक की बिक्री के मामले में, विद्युत घटक की कीमत वितरण लाइसेंसधारियों की औसत एकत्रित लागत से अधिक नहीं हो सकती है। विनियमों में यह भी प्रावधान किया गया था कि जनरेटर (अक्षय ऊर्जा के) बैंकिंग सुविधाओं, क्रॉस सब्सिडी अधिभार के भुगतान से छूट आदि सहित किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं थे।

अन्य चीजों के बीच। उल्लिखित प्रचार लाभ केवल आरई प्रमाणपत्रों के व्यापार और बिक्री के संदर्भ में लागू थे।

8. आर. ई. सी. विनियम 2010 में न्यूनतम मूल्य और सहनशीलता मूल्य अर्थात् क्रमशः न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य का प्रावधान किया गया है, जिस पर आर. ई. सी. का बिजली विनियम में कारोबार किया जा सकता है। ये हैं कीमतें ' आर. ई. सी. विनियम 2010 का विनियम 5 (1) (सी)।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यानी न्यूनतम मूल्य और सहनशीलता मूल्य पूरे देश के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने थे।

9. वर्तमान मामले में, राज्य आयोग अपने आदेश द्वारा

आदेश में अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (आर. पी. ओ.) को पूरा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए 3.56 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटे के तरजीही स्तर पर शुल्क का प्रावधान किया गया है। आदेश की "नियंत्रण अवधि" [दिनांक 30.1.2010] 11.08.2009 की अवधि के लिए थी 10.08.2012 1. आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अधिमान्य तंत्र के तहत तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए स्थापित पवन जनरेटरों के लिए निम्नलिखित प्रचार लाभ भी प्रदान करता है:

(क) राज्य में खुली पहुंच वाले उपयोगकर्ताओं को पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए क्रॉस सब्सिडी शुल्क से छूट।

(बी) अतिरिक्त भुगतान (15 मिनट के समय खंड में मासिक खपत के खिलाफ सेट ऑफ और उससे अधिक) को ऐसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए कमीशन द्वारा निर्धारित तरजीही शुल्क के 85 प्रतिशत की दर से संबंधित वितरण लाइसेंसधारी को बिक्री के रूप में माना जाएगा।

10. 17.04.2010 पर, राज्य आयोग ने गुजरात बिजली को अधिसूचित किया

विनियामक आयोग (अक्षय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 (इसके बाद "राज्य विनियम")। राज्य विनियमों में कुल खपत के प्रतिशत के लिए प्रावधान किया गया है कि वितरण लाइसेंसधारियों को आर. पी. ओ. से खरीदारी करनी थी और आगे यह स्वीकार किया कि आर. पी. ओ. को ऐसे आर. ई. सी. की खरीद से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, बाध्य निकाय दो स्रोतों के माध्यम से अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा कर सकते हैं:

10 आदेश संख्या 1/2010 1 में दिनांकित 30.01.2010 आदेश का प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है: " 2.2 नियंत्रण अवधि आयोग ने 11 अगस्त, 2006 के अपने आदेश संख्या 2 के माध्यम से तीन साल की अवधि यानी 10 अगस्त, 2009 तक के लिए पवन ऊर्जा शुल्क निर्धारित किया था। वर्तमान आदेश का मसौदा आईडी1 पर प्रकाशित किया गया था और इसे 1 जुलाई, 2009 से प्रभावी होने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, कुछ विरोधियों ने सुझाव दिया कि वर्तमान आदेश को पिछली नियंत्रण अवधि के अंत से प्रभावी बनाया जाए। चूंकि पिछली नियंत्रण अवधि 10 अगस्त, 2009 को समाप्त हो गई थी, इसलिए आयोग निर्णय लेता है कि इस आदेश के लिए नियंत्रण अवधि 11 अगस्त, 2009 से 3 (तीन) वर्ष की होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) अक्षय ऊर्जा की सीधी खरीद (तरजीही शुल्क पर)

राज्य आयोग द्वारा निर्धारित) और

(ख) न्यूनतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के बीच बाजार मूल्य पर आर. ई. सी. की खरीद

केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित सहनशीलता मूल्य

11. बिजली खरीद समझौता (इसके बाद "पी. पी. ए".)

आर. ई. सी. विनियम 2010, गुजरात ऊर्जा और पवन ऊर्जा डेवलपर्स (इसके बाद, "डब्ल्यू पी. डी".) के बीच दर्ज किया गया था, जिसमें 29.03.2012 पर प्रतिवादी आर. डब्ल्यू ई. भी शामिल था। इस समझौते में 25 वर्षों के लिए 2.64 प्रति इकाई शुल्क की सीमा का प्रावधान किया गया था। शुल्क के अलावा, डब्ल्यू पी. डी. उत्पादित और आपूर्ति की जाने वाली बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए आर. ई. सी. जारी करने के लिए पात्र थे उनके द्वारा अपीलार्थियों को। पीपीए में प्रवेश करने के समय डब्ल्यूपीडी (जैसे आरडब्ल्यूई, विश विंड आदि) के लिए उपलब्ध वैकल्पिक मार्ग राज्य आयोग द्वारा निर्धारित 3.56 रुपये प्रति यूनिट के प्रचार शुल्क पर बिजली बेचना था। विकल्प चुनकर, डब्ल्यूपीडी थे

2, 64 रुपये प्रति इकाई के साथ-साथ व्यापार योग्य आर. ई. सी. पर शुल्क सुनिश्चित किया गया, जिनकी कीमत "भारित औसत एकत्रित मूल्य" के आधार पर निर्धारित की गई थी। वितरण लाइसेंसधारियों को बिजली की ऐसी मात्रा को समायोजित करने में सक्षम बनाया गया था अधिनियम की धारा 86 (1) (ई) के तहत निर्दिष्ट आर. पी. ओ. के लिए खरीदा गया। इस प्रकार, उद्योग के दोनों क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा गया।

12. राज्य आयोग ने अपने दिनांक 08.08.2012¹³ के आदेश द्वारा

उस शुल्क का निर्धारण किया जिस पर बिजली की खरीद की जा सकती थी

11.08.2012 से 31.03.2016 तक की नियंत्रण अवधि में चालू की गई पवन ऊर्जा परियोजनाओं के वितरण लाइसेंसधारी और अन्य।

13. 11.07.2013 पर, केंद्रीय आयोग ने आर. ई. सी. में संशोधन किया

विनियम 2010 (इसके बाद "दूसरा संशोधन") और "बिजली खरीद की एकत्रित लागत से अधिक नहीं होने वाली कीमत पर" के साथ प्रतिस्थापित किया गया

संबंधित विवरण के साथ बिजली खरीद की एकत्रित लागत "14

12 आर. ई. सी. विनियम 2010 के विनियम 5 का स्पष्टीकरण देखें जो औसत एकत्रित मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"भारित औसत एकत्रित मूल्य जिस पर वितरण लाइसेंसधारी ने खरीदा है

सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से पिछले वर्ष में स्व-उत्पादन की लागत, यदि कोई हो, सहित बिजली, दीर्घकालिक और अल्पकालिक, लेकिन अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित स्रोतों को छोड़कर, जैसा भी मामला हो।

13 आदेश सं. 2/2012 14 में विनियमन 5 (सी) में प्रासंगिक संशोधन इस प्रकार है:

"(2) प्रधान विनियमों के विनियम 5 के खंड (1) के उपखंड (ग) में,

"ऐसे वितरण लाइसेंसधारी की बिजली खरीद की एकत्रित लागत से अधिक नहीं होने वाली कीमत पर" शब्दों को "उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित ऐसे वितरण लाइसेंसधारी की बिजली खरीद की एकत्रित लागत पर" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17 गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उक्त संशोधन के कारण। संशोधन में यह स्पष्ट किया गया था कि एपीसीसी से कम शुल्क पर इस संशोधन से पहले से ही निष्पादित पीपीए प्रभावित नहीं होंगे। पहले दो उत्तरदाता केंद्रीय आयोग के आदेश से व्यथित थे। उन्होंने याचिका दायर की 15

राज्य आयोग के समक्ष यह तर्क देते हुए कि आर. ई. सी. विनियमों में परिवर्तन को देखते हुए पी. पी. ए. की शर्तों को बदलना पड़ा। इस याचिका को राज्य आयोग द्वारा अनुमति दी गई थी जिसमें निर्देश दिया गया था कि केंद्रीय आयोग का आदेश सामान्य था और इसलिए सभी पर लागू होता था।

समान रूप से स्थित पवन ऊर्जा जनरेटर। राज्य आयोग के आदेश से व्यथित गुजरात ऊर्जा ने पहले एक अपील दायर की थी

एपीटीईएल। इस अपील को ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दिनांक 06.12.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करने वाले ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका को प्राथमिकता दी; वह भी ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दिनांक 24.07.2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थी के तर्क

14. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. ए.

पी. पी. ए. की पूरी अवधि (अर्थात् 25 वर्ष) और उन्हें राज्य आयोग द्वारा प्रतिस्थापित या पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता था। यह आगे तर्क दिया गया कि क्या अपीलकर्ताओं को साल-दर-साल आधार पर एपीसीसी के बारे में पता था समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय, उन्होंने आर. ई. सी. तंत्र को नहीं अपनाया होगा, बल्कि इसके बजाय एक अलग विधि का लाभ उठाया होगा जिसके तहत कीमतें निर्धारित की गई होंगी और अपीलकर्ता भी आर. पी. ओ. लाभों के हकदार होंगे।

15. रिलायंस को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था। सोलर सेमी-कंडक्टर पावर लिमिटेड

कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड "यह तर्क देने के लिए कि यदि राज्य आयोग पक्षों के बीच शुल्क को फिर से निर्धारित करता है, तो पीड़ित पक्ष

उक्त समझौते को जारी रखने या इस तरह के बढ़े हुए शुल्क पर एक नया समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

17 (2017) 14 एससीआर 115 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. अपीलकर्ताओं ने आगे कहा कि राज्य आयोग ने

पी. पी. ए. को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि इसे आर. ई. सी. विनियम 2010 के संदर्भ में दर्ज किया गया था जो केंद्रीय आयोग द्वारा तैयार किया गया था और इसके अनन्य अधिकार क्षेत्र में था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता अपने उपभोक्ताओं के प्रति अपने कर्तव्य में विफल हो जाएंगे यदि वे कम शुल्क के लिए बातचीत नहीं कर सकते हैं या यदि वे कम शुल्क पर बिजली की उपलब्धता के बावजूद उच्च शुल्क पर बिजली खरीदने के लिए सहमत हैं। ऐसी स्थिति में, इस तरह से लगाई गई बिजली की खरीद की उच्च लागत अंततः उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो अधिनियम के तहत एक निर्दिष्ट सार्वजनिक हित के विपरीत होगी।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि की परिभाषा

"वर्तमान मामले में ए. पी. पी. सी. पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और टैरिफ के लिए प्रश्रुत पी. पी. ए. प्रदान किया गया है। नतीजतन, किसी भी कानून या विनियम में पार्टियों के लिए इस तरह के शुल्क पर सहमत होने पर कोई रोक नहीं थी और वास्तव में, आर. ई. सी. विनियम 2010 ने खुद माना कि पी. पी. ए. "एकत्रित खरीद लागत से अधिक कीमत पर नहीं" हो सकता है। इसी तरह, ग्राहकों या लाइसेंसधारियों को ऐसी बिजली की बिक्री के लिए, "पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य" का संदर्भ दिया जाता है और इसलिए "पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य" का संदर्भ दिया जाता है।

इसका मतलब यह हो सकता है कि कीमत भी एक निश्चित कीमत हो सकती है और इसका मतलब यह नहीं है कि इसे हर साल गतिशील और अलग-अलग होना चाहिए।

18. यह तर्क दिया गया कि ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा दी गई व्याख्या नहीं है

विनियमों में किसी भी स्पष्ट प्रावधान, या आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न किसी भी चीज़ पर आधारित। विनियमों में परिवर्तन, जब तक कि विशेष रूप से पूर्व अवधि के लिए लागू नहीं किया जाता है, को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, [2013 में] संशोधन से पहले किए गए अनुबंधों को संशोधित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना न केवल संशोधित विनियमों की स्पष्ट शर्तों के विपरीत होगा, बल्कि पी. पी. ए. की शर्तों के भी विपरीत होगा जो विनियमों में इस तरह के परिवर्तन को समायोजित या प्रदान नहीं करते हैं।

19. अपीलकर्ताओं ने आगे आग्रह किया कि पी. पी. ए. जानबूझकर था

उत्तरदाताओं द्वारा 29.03.2012 पर दर्ज किया गया, जो इससे पहले था

18 पी. पी. ए. के खंड 1.1 के रूप में ए. पी. पी. सी. को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: औसत बिजली खरीद लागत "का अर्थ है भारत औसत एकत्रित मूल्य जिस पर वितरण लाइसेंसधारी के पास है। स्वयं की लागत सहित बिजली खरीदी

सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से पिछले वर्ष में दीर्घकालिक उत्पादन, यदि कोई हो, और अल्पकालिक; लेकिन अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित स्रोतों को छोड़कर, जैसा भी मामला हो। इसके अलावा, इस समझौते के लिए, समझौते की अवधि के लिए औसत बिजली खरीद लागत अनुच्छेद संख्या 5.2 गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड v के अनुसार होगी।

पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

राज्य आयोग का टैरिफ आदेश दिनांक 08.08.2012। पी. पी. ए. पर उत्तरदाताओं द्वारा 11.07.2013 से पहले (जब आर. ई. सी. विनियमों में संशोधन किया गया था) स्वेच्छा से बिना किसी आरक्षण के हस्ताक्षर किए गए थे। पी. पी. ए. की शर्तें बाध्यकारी और लागू करने योग्य थीं, जो संभावित रूप से लागू होने वाले दूसरे संशोधन से अप्रभावित थीं। विद्वान वकील ने इस संबंध में प्रकाशित कारण विवरण में सी. ई. आर. सी. द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर भरोसा किया। 19

20. यह तर्क दिया जाता है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का संकल्प दिनांक 28-01-2016 और शुल्क

नीति ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के सह-उत्पादन की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि यह अधिक अनुपात तक पहुंच सके। इस नीति का उद्देश्य निवेश बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि अक्षय ऊर्जा पैदा करने वाली व्यवहार्य इकाइयां स्थापित की जाएं।

21. यह तर्क दिया गया था कि पी. पी. ए. एक वाणिज्यिक लेनदेन था।

पार्टियों के बीच स्वतंत्र रूप से प्रवेश किया। न तो अपीलार्थी और न ही प्रथम प्रत्यर्थी पी. पी. ए. में प्रवेश करने के लिए बाध्य थे और न ही किसी विशिष्ट नियम या शर्तों से सहमत थे। यदि शर्तें स्वीकार्य नहीं थीं, तो दोनों पक्षों को लेनदेन को अस्वीकार करने और आर. ई. सी. विनियम 2010 के तहत प्रदान किए गए अन्य वैकल्पिक उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से बिजली बेचने या खरीदने की स्वतंत्रता थी। पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने के समय और उसके बाद भी दिसंबर 2013 के महीने में राज्य आयोग के समक्ष याचिका दायर करने तक (यानी डेढ़ साल से अधिक समय बाद) पी. पी. ए. का निष्पादन), प्रथम प्रत्यर्थी ने पी. पी. ए. के नियमों और शर्तों से सहमत होने के लिए कथित रूप से मजबूर या दबाव में रखे जाने पर कोई आपत्ति या विरोध नहीं उठाया। पी. पी. ए. की शर्तें पूरी तरह से आर. ई. सी. विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुपालन में थीं क्योंकि उन विनियमों में प्रतिबंध पूल बिजली खरीद लागत से अधिक कीमत के लिए नहीं था। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच सहमत मूल्य 2.64/- प्रति इकाई या एकत्रित बिजली खरीद थी।

बाद के वर्ष की लागत, जो भी कम हो।

19 दिनांकित 10.07.2013, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि "कुछ हितधारकों ने यह स्पष्ट करने का सुझाव दिया है कि क्या एपीपीसी से कम कीमत पर निष्पादित पीपीए आरईसी तंत्र के तहत अयोग्य हो जाएंगे। यह महसूस किया जाता है कि ए. पी. पी. सी. से कम या अधिक बिजली घटक के लिए शुल्क से आर. ई. जनरेटर को नुकसान या लाभ हो सकता है। आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि एपीपीसी से कम शुल्क पर पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजनाओं पर रोक लगाने का इरादा नहीं है। यह संशोधन संभावित रूप से लागू होगा और इस तरह "एपीपीसी से कम पर पहले से ही निष्पादित पीपीए" को प्रभावित नहीं करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. अपीलार्थियों का तर्क है कि 11.07.2013 तक कोई भी WPD/नहीं है।

उत्तरदाताओं ने पी. पी. ए. की पूरी अवधि के लिए ₹2.64/के. डब्ल्यू. एच. के शुल्क पर कोई भी मुद्दा उठाया। यह केवल 10.12.2013 पर था, पहले दो उत्तरदाताओं ने राज्य आयोग के समक्ष याचिका संख्या 1363/2013 दायर की और दावा किया कि शुल्क एक निश्चित दर के बजाय एपीपीसी लागत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर होना चाहिए।

2.64 / kWh। यह सीईआरसी के फैसले के विपरीत था

केवल संभावित रूप से दूसरे संशोधन का अनुप्रयोग-जो कि 11.07.2013 पर या उसके बाद दर्ज किए गए PPAS के लिए है। राज्य आयोग ने अपने आदेश (दिनांक 01.07.2015) द्वारा प्रत्यर्थी की याचिका की अनुमति दी और आगे निर्देश दिया कि आदेश प्रकृति में सामान्य है और सभी समान रूप से रखे गए डब्ल्यू. पी. डी. पर लागू होता है जिसकी पुष्टि पहले विवादित आदेश द्वारा की गई थी। अपीलार्थियों का तर्क है कि आर. ई. सी. तंत्र को अपनाने वाले पी. पी. ए. एस. के लिए शासी विनियम 2010 आर. ई. सी. विनियम हैं और राज्य आयोग इसके विपरीत शुल्क पर निर्णय नहीं ले सकता है। जब केंद्रीय आयोग ने स्पष्ट किया कि आई. डी. 1 से पहले किए गए पी. पी. ए. के लिए, पारस्परिक रूप से सहमत शुल्क पी. पी. ए. की पूरी अवधि (25 वर्ष) के लिए मान्य है, तो राज्य आयोग और ए. पी. टी. ई. एल. ने डब्ल्यू. पी. डी./उत्तरदाताओं के कहने पर एक नए शुल्क को प्रतिस्थापित करने में गलती की। यह बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बिजली नियम, 2005 का नियम 820 बाध्यकारी है, और विशेष रूप से केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क प्रदान करता है।

(सी. ई. आर. सी.) जी. ई. आर. सी./राज्य आयोग द्वारा पुनर्निर्धारण के अधीन नहीं होगा।

23. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यदि हस्ताक्षर करने के समय

पी. पी. ए. एस. डब्ल्यू. पी. डी. एस.-उत्तरदाताओं ने साल-दर-साल आधार पर ए. पी. पी. सी. में शुल्क की मांग की थी, अपीलकर्ताओं ने पी. पी. ए. एस. में प्रवेश नहीं किया होगा

आर. ई. सी. तंत्र मार्ग और केवल वैकल्पिक मार्ग को अपनाया होगा जहां कीमत तय की गई थी और इसके अलावा, अपीलार्थी आर. पी. ओ. लाभों के हकदार होंगे। यह भी स्पष्ट है क्योंकि अपीलकर्ताओं ने आर. ई. सी. तंत्र के तहत बिजली की खरीद के लिए दूसरे संशोधन के बाद किसी भी पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अपीलकर्ताओं का आग्रह है कि विवादित आदेश गुजरात ऊर्जा विकास निगम में इस अदालत के फैसले के विपरीत है

20 नियम 8 इस प्रकार है: " 8. धारा 79 के तहत उत्पादन करने वाली कंपनियों के शुल्क। - अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या (बी) के तहत उत्पादन करने वाली

कंपनियों के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क राज्य आयोग द्वारा पुनर्निर्धारण के अधीन नहीं होगा। अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ए) या (बी) के तहत कार्यों का प्रयोग करते हुए और उपरोक्त के अधीन राज्य आयोग यह निर्धारित कर सकता है कि क्या

राज्य में लाइसेंसधारक को केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर ऐसी उत्पादक कंपनियों के साथ बिजली खरीद समझौता या खरीद प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए। गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v.

पवन का नवीनीकरण करें

ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

लिमिटेड बनाम सोलर सेमी-कंडक्टर पावर कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड (सुप्रा)

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यदि राज्य आयोग शुल्क का पुनर्निर्धारण करता है, तो वह अपीलार्थियों को पी. पी. ए. जारी रखने या इस तरह के बढ़े हुए शुल्क के आधार पर अनुबंध करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि पी. पी. ए. को वैध रूप से निष्पादित करने वाले डब्ल्यू. पी. डी. शुल्क में वृद्धि या किसी अन्य नियम और शर्तों के लिए एक प्रचलित व्यवस्था के तहत पी. पी. ए. एस. में निहित शुल्क नियमों और शर्तों में संशोधन की मांग नहीं कर सकते हैं: वकील ने उपरोक्त विवाद के समर्थन में ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड बनाम साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड") "1; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम ईएमसीओ लिमिटेड (इसके बाद "एमको लिमिटेड ") 2 2; और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एसीएमई सोलर टेक्नोलॉजीज (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 23 का उल्लेख किया। 24. श्री सुंदरम ने अपीलार्थियों के लिए तर्क दिया कि डब्ल्यू. पी. डी. द्वारा की गई जबरदस्ती या दबाव या असमान सौदेबाजी आदि की याचिका निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट रूप से गलत थी: (क) राज्य आयोग के समक्ष याचिका केवल पहले दो प्रत्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी; इसलिए, यह सभी डब्ल्यू. पी. डी. के खिलाफ जबरदस्ती का आरोप लगाने का आधार नहीं हो सकता है; (ख) उक्त दो प्रत्यर्थियों द्वारा आरोप अस्पष्ट और अप्रमाणित थे, और एक विचार के बाद क्योंकि दिसंबर 2013 तक ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई थी, अर्थात्, संशोधित सी. ई. आर. सी. विनियमों के बाद तक; और (सी) जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, जबरदस्ती की ऐसी याचिका को विशेष रूप से अनुरोध और साबित करना था। इस संबंध में, आंध्र प्रदेश पारेषण निगम लिमिटेड (सुप्रा) पर निर्भरता रखी गई थी।

25. यह आगे तर्क दिया जाता है कि राज्य या केंद्रीय आयोगों का कोई विनियमन नहीं है जो पी. पी. ए. में शामिल किए जाने वाले शब्द को प्रतिबंधित करता है।

किसी भी पक्ष को आर. ई. सी. तंत्र से आर. ई. सी. में बदलने का विकल्प देता है।

अधिमान्य प्रशुल्क तंत्र। विवादित आदेश में एक पक्ष को अनुबंध रद्द करने की शक्ति देने वाले खंडों पर अपीलार्थियों द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों पर विचार नहीं किया गया था। इस संबंध में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम हार्टफोर्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2 4 और महारानी शांतिदेवी पी गायकवाड़ बनाम सावजीबाई हरिबाई पटेल और अन्य 2 5 पर निर्भरता रखी गई है।

21 (2010) 8 एससीआर 636

22 (2016) 1 एससीआर 857

23 (2017) 16 एससीसी 498

24 आकाशवाणी 1965 एससी 1288

25 5 2001 (5) एससीसी 101 [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ

26. श्री श्याम दीवान और श्री ध्रुव मेहता, पहले दो उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने आग्रह किया कि राज्य

वर्तमान मामले में आयोग का अधिकार क्षेत्र था। रिलायंस को पीपीए (अनुच्छेद 1.1) के परिभाषित खंड पर रखा गया था ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि

आयोग का अर्थ था 'राज्य आयोग'। यह आग्रह किया गया कि मौजूदा नियामक ढांचे (जो उपयुक्त आयोग द्वारा नियामक निरीक्षण के लिए प्रदान किया जाता है) के संदर्भ में, उत्पादक कंपनियों और वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा निष्पादित पी. पी. ए. को आवश्यक रूप से उपयुक्त द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कमीशन। सबसे पहले, अधिनियम की धारा 86 (1) (बी) विशेष रूप से राज्य आयोग को बिजली खरीद को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है।

और वितरण लाइसेंसधारियों की खरीद प्रक्रिया, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है जिस पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से खरीदी जाएगी। यह प्रावधान राज्य आयोग को विनियामक ढांचे के अनुसार उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पी. पी. ए. की शर्तों को संशोधित करने, बदलने या बदलने का अधिकार देता है। दूसरा, राज्य आयोग द्वारा अधिसूचित बहु-वर्षीय शुल्क विनियम, 2011 (इसके बाद "जी. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम") के तहत, पी. पी. ए. को अनिवार्य रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रभावी और लागू करने योग्य माना जा सके। विद्वान वकील ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक के प्रावधानों पर भरोसा किया

आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2019, (विनियम 21); दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग व्यापक (विद्युत का संचालन)

व्यवसाय) विनियम 2001 (विनियम 45) और आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारी) विनियम, 2013 (विनियम 36) इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि पी. पी. ए. की पूर्व फाइलिंग और अनुमोदन आवश्यक है और इस मामले में नहीं किया गया था, जो

इसकी कानूनी प्रभावशीलता को कम करता है।

27. यह प्रस्तुत किया गया था कि एकत्रित खरीदी गई बिजली की लागत

आर. ई. सी. तंत्र के तहत पिछले वित्तीय वर्ष की ए. पी. पी. सी. को ध्यान में रखा जाना चाहिए-जिसे नियमित रूप से संशोधित/बढ़ाया जाना चाहिए। जब एकत्रित खरीद लागत बढ़ती है, तो आर. ई. सी.

का न्यूनतम मूल्य कम हो जाएगा क्योंकि न्यूनतम मूल्य और आर. ई. सी. का स्थायी मूल्य कम हो जाएगा।

प्रत्येक नियंत्रण अवधि के अंत में उतार-चढ़ाव के अधीन। इस प्रकार, आर. ई. सी. तंत्र के तहत पवन ऊर्जा परियोजनाएं तभी व्यवहार्य होंगी जब

आर. ई. सी. की कीमतों में कमी की भरपाई के लिए बिजली घटक से प्राप्ति बढ़ जाती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि ए. पी. पी. सी. की गणना आर. ई. सी. मूल्य सीमा के निर्धारण के लिए सी. ई. आर. सी. द्वारा ली गई गणना से कम है, तो आर. ई. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिए व्यवहार्यता अंतर की समस्या हो सकती है।

पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आर. ई. सी. तंत्र के तहत जनरेटर, विशेष रूप से उन मामलों में जहां बिजली विनिमय में पाई जाने वाली कीमत न्यूनतम मूल्य के करीब है। 28. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि आर. ई. सी. विनियमों के दूसरे संशोधन ने विशेष रूप से "अधिकतम मूल्य पर" से "एकत्रित लागत पर" शब्दों को बदल दिया, जिसका अर्थ था कि खरीदी गई बिजली की लागत न तो बिजली खरीद लागत से कम हो सकती है और न ही अधिक। वकील ने दूसरे संशोधन के संबंध में केंद्रीय आयोग द्वारा जारी किए गए कारण विवरण पर भरोसा करते हुए कहा कि आर. ई. सी. अनुबंध निश्चित मूल्य अनुबंध नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे आर. ई. सी. परियोजनाओं की व्यवहार्यता को प्रभावित करेंगे क्योंकि मूल्य सीमा (न्यूनतम मूल्य/सहनशीलता मूल्य) आवधिक संशोधन के अधीन है। उक्त के प्रासंगिक उद्धरण

कारणों का विवरण नीचे दिया गया है:

" 4.3 विश्लेषण और निर्णय

कुछ हितधारकों ने स्पष्ट करने का सुझाव दिया है कि

एपीपीसी से कम पर पहले से ही निष्पादित पी. पी. ए. को प्रभावित नहीं करेगा। प्राप्त सुझाव के संबंध में कि बिजली का पीपीए

घटक एक निश्चित मूल्य दीर्घकालिक अनुबंध (बिना वृद्धि के) होना चाहिए क्योंकि आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली में आर. ई. सी. मूल्य सीमा निर्धारित करते समय निश्चित मूल्य ग्रहण किया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल्य सीमा आवधिक संशोधन के अधीन है; इसलिए निश्चित ए. पी. पी. सी. या बिना वृद्धि के दीर्घकालिक अनुबंध आर. ई. परियोजनाओं की व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकता है। किसी भी मामले में प्रस्तावित संशोधन में प्रावधान है कि एपीपीसी का निर्धारण उपयुक्त द्वारा किया जाएगा

आयोग "

और वितरण लाइसेंसधारियों को उपयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए आयोग; और यह कि विचाराधीन पी. पी. ए. को कभी भी राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और न ही अपीलकर्ताओं ने इस तरह के अनुमोदन के लिए राज्य आयोग से संपर्क किया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि न्यूनतम मूल्य और सहनशीलता [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मूल्य का निर्धारण विभिन्न सिद्धांतों, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों में एपीपीसी में भिन्नताओं (जिसे वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है) द्वारा निर्देशित किया जाना है। इसलिए, ए. पी. पी. सी. एक स्थिर अवधारणा नहीं हो सकती है अन्यथा न्यूनतम मूल्य या सहनशीलता मूल्य में भिन्नता से कम वसूली होगी।

जनरेटर।

कृत्रिम रूप से और राज्य आयोग की मंजूरी के बिना, यह उत्पादन करने वाली कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए आर. ई. सी. तंत्र के एक विषम अनुप्रयोग की ओर ले जाएगा, जिससे आर. ई. जनरेटर की कम वसूली और व्यवहार्यता नहीं होगी। 31. यह तर्क दिया गया कि आर. ई. सी. विनियम 2010 के विनियम 9 (2) में न्यूनतम मूल्य (न्यूनतम मूल्य) के निर्धारण का प्रावधान है और

सहनशीलता मूल्य (अधिकतम मूल्य) जिसके भीतर आर. ई. सी. का बिजली विनिमय में व्यापार किया जा सकता है। सी. ई. आर. सी. द्वारा पूरे देश के लिए न्यूनतम मूल्य और सहनशीलता निर्धारित की जानी है जो विभिन्न नियमों द्वारा निर्देशित है।

सिद्धांतों, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों में एपीपीसी में भिन्नता, जिसे वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है। इसलिए, यदि ए. पी. पी. सी. को स्थिर कर दिया जाता है तो आधार मूल्य/सहनशीलता मूल्य में भिन्नता से कम वसूली होगी। जनरेटर के लिए।

32. आर. ई. सी. तंत्र के तहत ध्यान में रखी जाने वाली ए. पी. पी. सी. गतिशील होनी चाहिए और इसे नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। जब ए. पी. पी. सी. को बढ़ाया जाता है, तो आर. ई. सी. का न्यूनतम मूल्य कम हो जाता है और इसके विपरीत और यह हर साल परिवर्तन के अधीन होता है। आर. ई. सी. मूल्य निर्धारण के साथ ए. पी. पी. सी., बिजली की आपूर्ति के लिए निर्धारित और अनुमोदित शुल्क है। दूसरे शब्दों में, ए. पी. पी. सी. और आर. ई. सी. मूल्य निर्धारण एक ही पूरे के दो आधे हिस्से हैं, जो समग्र शुल्क का गठन करते हैं जो आर. ई. सी. तंत्र के तहत पंजीकृत एक उत्पादक कंपनी का अधिकार है।

प्राप्त करने के लिए। आर. ई. सी. मूल्य निर्धारण के साथ ए. पी. पी. सी. को पी. पी. ए. में शुल्क खंड के हिस्से के रूप में शामिल करने का इरादा था। अगर कोई भी घटक को कृत्रिम रूप से निर्धारित या सीमित किया जाता है, और वह भी जी. ई. आर. सी. से अनुमोदन के बिना, यह उत्पादन करने वाली कंपनी के नुकसान के लिए आर. ई. सी. तंत्र के एक विषम अनुप्रयोग की ओर ले जाएगा, जिससे आर. ई. जनरेटर की कम वसूली और व्यवहार्यता नहीं होगी।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

33. यह प्रस्तुत किया गया था कि पी. पी. ए. में शुल्क मूल विनियमन का उल्लंघन था, जो एक निश्चित दीर्घकालिक पर विचार नहीं करता है।

मूल्य/शुल्क। इसलिए, यह अवैध है और इसे विनियमन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ए. पी. टी. ई. एल. ने शुल्क को विनियमन के साथ सही ढंग से संरेखित किया। विनियमन को चुनौती नहीं दी गई है और इसमें कानून का बल है और यह अनिवार्य करता है कि पी. पी. ए. एस. को विनियमों के अनुरूप होना चाहिए। रिलायंस को पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम पर रखा गया है। सी. ई. आर. सी. (इसके बाद "पी. टी. सी. इंडिया") 26.

34. तीसरे प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि उत्पादन करने वाली कंपनी और वितरण लाइसेंसधारी के बीच शुल्क नहीं हो सकता है। एक पी. पी. ए. जो सी. ई. आर. सी. विनियमों और शुल्क के अनुरूप नहीं था

अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देती है तरजीही मूल्य निर्धारण।

35. विश विंड के वकील ने कहा कि यह पी. पी. ए. की कठिन शर्तों से बंधा नहीं हो सकता क्योंकि इसे कभी भी राज्य द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

36. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 86 (1) (बी) राज्य आयोग को समझौते की शर्तों को संशोधित करने, बदलने या बदलने का अधिकार देती है अधिनियम के तहत स्थापित नियामक ढांचे के अनुसार पी. पी. ए. का अनुपालन सुनिश्चित करना। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि एपीपीसी की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि न्यूनतम मूल्य

26 (2010) 3 एस. सी. आर. 609 [2023] 7 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और सहनशीलता मूल्य गतिशील प्रकृति के होते हैं और ए. पी. पी. सी. को न्यूनतम मूल्य से जोड़ा जाता है और सहनशीलता मूल्य भी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है ताकि उत्पादकों को गारंटीकृत वापसी प्रभावित न हो।

विश्लेषण और निष्कर्ष

37. जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग से उत्पन्न संकट और भारी पर्यावरणीय लागत ने सरकारों, दुनिया को प्रेरित किया है।

ऊर्जा के वैकल्पिक और नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना। डेढ़ दशक में अक्षय ऊर्जा के तेजी से विकास ने देखा है कि सौर और पवन ऊर्जा अब देश में ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत हैं।

दुनिया के कई देश। एक समय हरित ऊर्जा एक महंगा विकल्प था, लेकिन अब यह ऊर्जा बिलों को कम करने में मदद कर रहा है।

38. ऐसे स्रोतों की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था ने केंद्र सरकार को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया है कि सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कर सकते हैं

उत्पादन स्थानीय वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति को और प्रभावित करेगा। वर्षों से भारत ने अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक नीति और नियामक ढांचा स्थापित किया है विकास। भारत ने 1990 के दशक में पवन ऊर्जा का विकास शुरू किया और पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्षमता में काफी वृद्धि की है। पवन ऊर्जा क्षमता वाले स्थापित देशों की तुलना में

संयुक्त राज्य अमेरिका या डेनमार्क, भारत देर से आने वाला देश है। फिर भी, पवन ऊर्जा के लिए इसका समर्थन,

अपनी नीतियों के माध्यम से भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ उत्पादक बन गया है; भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में पवन ऊर्जा का योगदान 10 प्रतिशत है। फरवरी 2023 तक, भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 42,015 मेगावाट (मेगावाट) थी। 27

39. अधिनियम की धारा 86 राज्य के कार्यों की गणना करती है।

आयोग; धारा 86 (1) (ई) निम्नानुसार है:

27 भौतिक प्रगति (उपलब्धियाँ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। भारत से। [HTTPS: //एमएनआरई. गव. इन/द-मिनिस्ट्री/फिजिकल-प्रोग्रेस](https://एमएनआरई.गव.इन/द-मिनिस्ट्री/फिजिकल-प्रोग्रेस), 20 बजे 06.04.2023 पर देखा गया: 30 घंटे।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" धारा 86 (1): राज्य आयोग इसका निर्वहन करेगा

निम्नलिखित कार्य, अर्थात्:

*

**

(ई) उपयुक्त उपाय प्रदान करके अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली के सह-उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना।

ग्रिड के साथ संपर्क और किसी को भी बिजली की बिक्री के लिए

व्यक्ति, और यह भी निर्दिष्ट करें, ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए, बिजली की कुल खपत का प्रतिशत

वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में; "

40. राज्य आयोगों ने नियमों का विकास करते समय इस महत्वपूर्ण खंड के अंतिम भाग पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। अपने अधिकार क्षेत्र में वितरण लाइसेंसधारी। अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शुल्क नीति में निम्नानुसार कहा गया है:

" खंड 4: ऊर्जा उत्पादन के गैर-पारंपरिक स्रोत

सह-पीढ़ी सहित:

(1) अधिनियम की धारा 86 (1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार,

उपयुक्त आयोग न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करेगा -

ऐसे स्रोतों से ऊर्जा की खरीद

क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की उपलब्धता और खुदरा शुल्क पर इसका प्रभाव। ऊर्जा की खरीद के लिए इस तरह के प्रतिशत को निर्धारित किए जाने वाले शुल्कों के लिए लागू किया जाना चाहिए

एस. ई. आर. सी. 1 अप्रैल, 2006 तक नवीनतम। "

आर. ई. सी. विनियम 2010 के विनियम 4 (1) के आधार पर, आर. ई. सी. की दो श्रेणियां हैं: सौर और गैर-सौर। विनियम 4 (2)

आदेश देता है कि "गैर-सौर प्रमाण पत्र को बाध्य संस्थाओं को बेचा जाएगा ताकि वे उनसे खरीद के लिए अपने दायित्व को पूरा कर सकें। सौर ऊर्जा के अलावा अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोत"। आर. ई. सी. विनियमों (पहले निकाले गए) के विनियम 5 (1) में अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए आवेदन करने और प्रमाणपत्रों के लिए पंजीकरण लेने के लिए पात्रता शर्तों का उल्लेख किया गया है; ये वे हैं जो कंपनी के पास होने चाहिए: (क) राज्य एजेंसी से मान्यता प्राप्त; (ख) उचित एजेंसी द्वारा निर्धारित अधिमान्य शुल्क पर बिजली बेचने के लिए ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता के लिए कोई बिजली खरीद समझौता नहीं है।

कमीशन; और (ग) यह या तो उत्पन्न बिजली बेचता है-(i) उस क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी को जिसमें पात्र संस्था स्थित है, ऐसी [2023] 7 एस. सी. आर. की बिजली खरीद की एकत्रित लागत से अधिक कीमत पर नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर उपभोक्ता, या बिजली विनिमय के माध्यम से बाजार निर्धारित मूल्य। "एकत्रित लागत या खरीद" का क्या अर्थ है

स्पष्टीकरण (विनियमन 5) में विस्तृत रूप से इसका अर्थ है "भारित औसत एकत्रित मूल्य जिस पर वितरण लाइसेंसधारी के पास है।

पिछले वर्ष सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से स्व-उत्पादन लागत, यदि कोई हो, सहित बिजली दीर्घावधि के लिए खरीदी और

अल्पकालिक, लेकिन अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित स्रोतों को छोड़कर।

जैसा कि मामला हो सकता है "।

41. आर. ई. सी. विनियम 2010 के उद्देश्यों को इस अदालत के फैसले में वर्णित किया गया था, जिसे हिंदुस्तान जिक के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

लिमिटेड वी. राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, 28

" 44. [.....] प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाए गए हैं।

बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने का उद्देश्य

ऊर्जा के प्रदूषणकारी स्रोतों के विपरीत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से जो सिद्धांत अधिनियम में निहित है,

2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति और 2005 की शुल्क नीति

2006. न्यूनतम खरीद की आवश्यकता वाले प्रावधान

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का प्रतिशत है

पर्यावरण की रक्षा करने और इसे रोकने के लिए संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था

अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके क्षेत्र में प्रदूषण

व्यापक जनहित में जितना संभव हो सके। [.....] "

42. इसलिए, इस न्यायालय के दृष्टिकोण को ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने की नीति के उद्देश्य, आर. ई. सी. शुरू करने के उद्देश्य और लाइसेंसधारियों पर रखे गए प्रगतिशील दायित्वों पर विचार करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे "हरित" या "स्वच्छ" स्रोतों से ऊर्जा की खरीद व्यवहार्य तरीके से करें। वर्तमान मामले में, अक्षय ऊर्जा की खरीद का दायित्व गुजरात विद्युत में स्थित है।

विनियामक आयोग (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 (इसके बाद नवीकरणीय स्रोत)

नियम ")। उक्त नवीकरणीय स्रोत विनियमों का विनियम 4 (1) इस प्रकार है:

" 4. अक्षय खरीद दायित्व की मात्रा (आर. पी. ओ.)

4.1 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी बिजली खरीदेगा।

के. डब्ल्यू. एच.) अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, एक परिभाषित न्यूनतम पर

28 (2015) 7 एस. सी. आर. 1104 जरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। पवन का नवीनीकरण करें। एनईआरजीवाई (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इसके उपभोक्ताओं की कुल खपत का प्रतिशत

एक वर्ष के दौरान टी एंड डी नुकसान। इसी तरह, कैप्टिव और ओपन एक्सेस

उपयोगकर्ता (ओं)/उपभोक्ता (ओं) से बिजली (के. डब्ल्यू. एच. में) खरीदेंगे।

अक्षय ऊर्जा स्रोत, एक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत पर

एक वर्ष के दौरान उसकी कुल खपत।

निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत तालिका में नीचे दिए गए हैं। 1 .

तालिका 1

वर्ष

अक्षय ऊर्जा से खरीद की न्यूनतम मात्रा (% में)

ऊर्जा स्रोत (किलोवाट घंटे में ऊर्जा के संदर्भ में)

सौर ऊर्जा

बायोमास,

कुल

हवा।

बैगैस और

(1)

(2)

(3)

(4)

अन्य

(5)

	5 %		
		4.5 %	
			0.25 %
			0.25 %
	6 %		
			0.5 %
		0.5 %	
		5.0 %	
2011-12	2012-13		
	7 %		
		1.0 %	
			0.5 %
		5.5 %	

यदि ऊपर उल्लिखित बिजली खरीद की न्यूनतम मात्रा
सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध नहीं हैं।

किसी विशेष वर्ष में, फिर ऐसे मामलों में, अतिरिक्त हवा या
अन्य ऊर्जा, जो कॉलम 3 और 5 में दिखाई गई है,

स्तम्भ 2. बशर्ते कि अक्षय खरीद के लिए ऐसी बाध्यता
ऊर्जा में खरीद, यदि कोई हो, शामिल होगी।

अक्षय ऊर्जा स्रोत पहले से ही बाध्य द्वारा बनाए जा रहे हैं संबंधित इकाई:

बशर्ते कि बिजली के तहत बिजली की खरीद

अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए समझौते

वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा पहले से ही दर्ज किए गए स्रोत

उनकी वर्तमान वैधता तक जारी रखा जाना, भले ही कुल

इस तरह के समझौतों के तहत खरीद प्रतिशत से अधिक है

यहाँ ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। '

43. नवीकरणीय स्रोतों के विनियम 9 (1) के संदर्भ में

दान, यदि कोई बाध्य निकाय (जैसे कि वर्तमान अपीलार्थी) करता है

विनियमों में दिए गए अक्षय खरीद दायित्व को पूरा करें

विनियमन 2 (के) में बाध्य इकाई को "के तहत अनिवार्य इकाई" के रूप में परिभाषित किया गया है
(ई) (विद्युत) अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के तहत अक्षय ऊर्जा को पूरा करने के लिए

इन विनियमों के खंड 3 के तहत दायित्व और पहचान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी वर्ष के दौरान और प्रमाण पत्र भी नहीं खरीदता है, राज्य आयोग बाध्य इकाई को अलग से जमा करने का निर्देश दे सकता है। ऐसी बाध्यकारी संस्था द्वारा सृजित और अनुरक्षित की जाने वाली निधि, ऐसी राशि जो राज्य आयोग निर्धारित करे। इस प्रकार, बाध्य निकाय,

(वितरण लाइसेंस शामिल थे) अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की खरीद को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए कदम उठाने पड़े। इसे प्रोत्साहित करने के लिए, लचीलापन दिया गया था; बिजली उत्पादक या तो राज्य आयोग के शुल्क निर्धारण आदेश के अनुसार शुल्क तय कर सकते हैं, या एक अन्य तंत्र अपना सकते हैं, यानी आर. ई. सी. विनियमों में विचार किया गया है।

44. इस मामले में पी. पी. ए. में निर्धारित प्रासंगिक शर्तें और शर्तें नीचे दी गई हैं:

" दरें और शुल्क

5.1 मासिक ऊर्जा शुल्क: जी. यू. वी. एन. एल. इस समझौते की अवधि के लिए गुजरात एस. एल. डी. सी. के एस. ई. ए. द्वारा प्रमाणित वितरित ऊर्जा के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की वाणिज्यिक संचालन तिथि, जो भी बाद में हो, से हर महीने बिजली उत्पादक को भुगतान करेगा। खरीदी गई ऊर्जा के लिए जी. यू. वी. एन. एल. द्वारा देय शुल्क खंड 5 के अनुसार होगा।

5.2 . जी. यू. वी. एन. एल. रुपये की एक निश्चित दर का भुगतान करेगी। 2.64 मासिक राज्य ऊर्जा खाते (एस. ई. ए.) में गुजरात एस. एल. डी. सी. द्वारा प्रमाणित वितरित ऊर्जा के लिए इस समझौते की अवधि के दौरान प्रति के. डब्ल्यू. एच. (पिछले वित्त वर्ष के लिए औसत बिजली खरीद लागत अर्थात् 2010-11): क) बाद के किसी भी वित्त वर्ष में ए. पी. पी. सी. ए. पी. पी. सी. से नीचे चला जाता है जो वित्त वर्ष 2010-11 के ए. पी. पी. सी. से नीचे चला जाता है, जो सुनिश्चित करने के लिए लागू शुल्क है। वित्त वर्ष इतना कम एपीपीसी होगा कि

पिछले साल।

ख) बिजली उत्पादक और बिजली खरीदार दोनों के पास 23.10 मेगावाट डब्ल्यूटीजीएस के चालू होने के 10 साल बाद आरईसी तंत्र से तरजीही शुल्क में बदलने का विकल्प है। मामले में

कोई भी पक्ष विकल्प का उपयोग करता है, शुल्क रुपये होगा। 3.56 प्रति के. डब्ल्यू. एच. (जैसा कि जी. ई. आर. सी. द्वारा आदेश सं. 1 समझौते की शेष अवधि के लिए 2010 का दिनांक 30.1.2010)।

इसके अलावा, बिजली उत्पादक आर. ई. सी. जे. ए. आर. ए. टी. यू. आर. जे. आर. जे. ए. वी. के. विकास निगम लिमिटेड से पवन परियोजना के डी-रजिस्ट्रेशन के लिए जी. यू. वी. एन. एल. को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

पवन का नवीनीकरण करें एनईआरजीवाई (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

किसी भी पक्ष के अभ्यास के मामले में तंत्र। आर. ई. सी. से तरजीही शुल्क में बदलने का विकल्प।

5.3 ग्रिड से लिए गए प्रत्येक केवीआरएच के लिए, कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित दर पर जीईटीसीओ को भुगतान करेगी।

समय-समय पर तैयार किए गए प्रत्येक केएआरएच के लिए।

5.4 जब तक अंतर-राज्य एबीटी लागू नहीं किया जाता है, तब तक पवन टरबाइन के उत्पादन हिस्से के लिए जीईडीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र

मासिक ऊर्जा बिल के लिए स्वीकार्य। इस समझौते में दिखाई देने वाले अंतरराज्यीय एबीटी और ओपन एक्सेस विनियमों के अन्य प्रावधान भी अंतरराज्यीय एबीटी के लागू होने के बाद ही लागू होंगे।

**

अनुच्छेद 9

अवधि, समाप्ति और चूक

25 (पैंचिश) वर्ष की अवधि पूरी होने तक वाणिज्यिक संचालन की तारीख "।

क्या वर्तमान मामले में पी. पी. ए. को पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी

कमीशन

45. आर. डब्ल्यू. ई. और अन्य उत्तरदाताओं का आग्रह है कि पी. पी. ए. लागू किया जा सकता था क्योंकि इसे राज्य आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। न्यायालयक विचार अच्छे जे तर्क अपरिवर्तित आ अस्थिर अच्छे।

46. अक्षय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद से संबंधित राज्य आयोग के विनियम (अक्षय स्रोत राशन),

विशेष रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार है:

" 3. नवीकरणीय खरीद दायित्व की प्रयोज्यता: ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे: (1) वितरण लाइसेंसधारी (2) कोई भी

बिजली का उपभोग करने वाला अन्य व्यक्ति [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ii) पारंपरिक पीढ़ी से खुले माध्यम से प्राप्त किया गया अभिगम और तृतीय पक्ष बिक्री "।

47. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई प्रावधान कभी नहीं था, जो राज्य द्वारा पूर्व अनुमोदन को अनिवार्य करता हो।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करते हुए पार्टियों द्वारा किए गए पी. पी. ए. का आयोग। वास्तव में, अक्षय ऊर्जा के मामले में, राज्य आयोग ने एक मॉडल पीपीए को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, शुल्क के नियम और शर्तें केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि राज्य आयोग द्वारा। इन्हें मॉडल पी. पी. ए. में शामिल किया गया है। वर्तमान अपीलों में सुनवाई के दौरान न तो आयोग और न ही चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी, वर्तमान मामले में पी. पी. ए. में किसी भी प्रावधान को इंगित करने में सक्षम थे, जो

मॉडल पी. पी. ए. के किसी भी प्रावधान, या किसी भी स्पष्ट विनियमन के साथ विरोधाभासी।

इसके अलावा, यह स्थापित नहीं किया गया था कि बहु-वर्षीय शुल्क विनियमों के किसी भी संदर्भ के अभाव में, वे पी. पी. ए. एस. पर कैसे लागू थे।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित।

48. इस न्यायालय का यह भी विचार है कि पी. पी. ए. के पूर्व अनुमोदन को निर्धारित करने वाले विशिष्ट मानदंडों के अभाव में जैसे कि

महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2019 के विनियम 21 के प्रावधान; दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के विनियम 45 का व्यापक (

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्ति) विनियम, 2013 के विनियम 2001 और विनियम 36, इस पहलू पर प्रत्यर्थी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष, जो राज्य विनियमों के प्रावधानों के तहत किसी भी निर्धारित दायित्वों पर आधारित नहीं हैं, इसके संचालन के लिए राज्य आयोग की मंजूरी की आवश्यकता होती है, को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

क्या आर. ई. सी. विनियमों में परिवर्तन इस मामले में पी. पी. ए. के संशोधन को बाध्य करता है

49. एमको लिमिटेड (उपरोक्त) में, पार्टियों ने सौर ऊर्जा की बिक्री और खरीद के लिए 09.12.2010 पर एक पीपीए में प्रवेश किया था। पीपीए था

इकाई के स्थान में कुछ कठिनाइयों को देखते हुए 07.05.2011 पर संशोधित किया गया। जब पी. पी. ए. लागू किया गया था, तो शुल्क आदेश लागू था। इस प्रकार पी. पी. ए. को पहले की नियंत्रण अवधि के दौरान प्रवेश किया गया था।

शुल्क आदेश। दूसरा शुल्क आदेश 27.01.2012 पर लागू हुआ।

यह गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आयकर के तहत त्वरित मूल्यहास की खरीद और लाभ उठाने के लिए कुछ रियायतें दी गईं और खरीदारों को ऐसे लाभ और बिजली खरीदारों को देय शुल्क नहीं दिए गए जो त्वरित मूल्यहास का लाभ नहीं लेते थे। प्रतिवादी एमको ने त्वरित मूल्यहास का लाभ नहीं उठाया था। इसके बावजूद, यह निकट आ गया

गुजरात राज्य आयोग ने नए सिरे से शुल्क के निर्धारण की मांग करते हुए तर्क दिया कि स्थिति बदल गई है। इस अदालत ने देखा कि बिजली खरीदार ने तर्क दिया था कि इसके बावजूद उसने प्रवेश किया नियंत्रण अवधि के दौरान पी. पी. ए., पी. पी. ए. में निर्दिष्ट मूल्य पर वितरक को बिजली बेचने के लिए बाध्य नहीं था और कानूनी रूप से अलग शुल्क निर्धारित करने की मांग करने का हकदार था। अदालत ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए तर्क को खारिज कर दिया। फैसले के प्रासंगिक उद्धरण (इन एमको लिमिटेड) नीचे दिए गए हैं:

" 11. प्रथम प्रत्यर्थी का मामला यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि उसने प्रथम प्रशुल्क आदेश में निर्दिष्ट "नियंत्रण अवधि" के दौरान पी. पी. ए. में प्रवेश किया है, वह अपीलार्थी को अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट मूल्य पर शक्ति बेचने के लिए बाध्य नहीं है।

पी. पी. ए. और कानूनी रूप से मांग करने का हकदार है (दूसरे से)

प्रतिवादी) एक अलग शुल्क का निर्धारण। यह पहले प्रत्यर्थी का आगे का मामला है कि पी. पी. ए. के तहत, अपीलकर्ता 25 साल की अवधि के लिए पहले प्रत्यर्थी से बिजली खरीदने के लिए बाध्य है यदि पहला प्रत्यर्थी "नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू करता है और उसके द्वारा खरीदी गई बिजली के लिए भुगतान करने के लिए भी बाध्य है।

पी. पी. ए. के अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट दरों पर। लेकिन पी. पी. ए. के अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट दरों पर अपीलार्थी को उसके द्वारा उत्पन्न बिजली बेचने का पहला प्रत्यर्थी का दायित्व केवल दो आकस्मिकताओं के होने पर अस्तित्व में आता है अर्थात् पहला प्रत्यर्थी (i) पहले टैरिफ आदेश के तहत निर्धारित "नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू करना; और (ii) आयकर अधिनियम के तहत "त्वरित मूल्यहास का लाभ" प्राप्त करना। प्रथम प्रत्यर्थी के अनुसार, प्रथम प्रशुल्क आदेश के तहत यह शर्त कि उसके तहत निर्धारित प्रशुल्क उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होता है जिन्हें ऐसा लाभ नहीं मिलता है, आयोग उस संबंध में एक याचिका पर सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक अलग प्रशुल्क का निर्धारण करेगा।

से "नहीं" का मतलब केवल यह होगा कि प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्धारित शुल्क उन परियोजनाओं/बिजली [2023] 7 एस. सी. आर. पर लागू नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्पादक जो त्वरित लाभ का लाभ नहीं उठाते हैं

अवमूल्यन "आयकर अधिनियम के तहत।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

13. हम पहले ही देख चुके हैं कि पहले उत्तरदाता ने नहीं किया

"नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू करें प्रथम शुल्क आदेश के तहत
निर्धारित किया गया और इसका लाभ भी नहीं उठाया गया

आय के तहत "त्वरित मूल्यहास का लाभ"

कर अधिनियम। यह सभी हाथों से स्वीकार किया जाता है कि "का लाभ

त्वरित मूल्यहास "प्रथम प्रशुल्क आदेश में उल्लिखित है

और पी. पी. ए. की धारा 32 (1) (i) में निहित शर्त है

आयकर अधिनियम को आयकर के नियम 5 (1-ए) के साथ पढ़ा जाता है नियम। वे विधि और
तरीके के लिए प्रदान करते हैं जिसमें

निर्धारिती की परिसंपत्तियों के मूल्यहास की गणना की जानी है।

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

26. इसके अलावा, तत्काल न्यायाधिकरण का निष्कर्ष

मामला गलत है। सबसे पहले पी. पी. ए. कोई विकल्प नहीं देता है

निर्माता द्वारा इसे चालू नहीं करने की संभावना की कल्पना करता है प्रथम के तहत निर्धारित
"नियंत्रण अवधि" के भीतर परियोजना

शुल्क आदेश और यह प्रदान करता है कि ऐसी स्थिति में क्या
द्वारा बिजली की बिक्री पर लागू शुल्क होना चाहिए
प्रथम उत्तरदाता। दूसरा, पी. पी. ए. पहले को "हकदार" नहीं बनाता है।
"दूसरे द्वारा निर्धारित शुल्क" के लिए उत्तरदाता
दूसरे प्रशुल्क आदेश द्वारा प्रत्यर्थी। दूसरी ओर,
पी. पी. ए. स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि ऐसी स्थिति में:
" उपरोक्त शुल्क चालू की गई सौर परियोजनाओं पर लागू होगा
या 31-12-2011 से पहले। सौर ऊर्जा के चालू होने की स्थिति में
परियोजना में 31-12-2011 से आगे देरी हुई है, GUVNL भुगतान करेगा
सौर परियोजनाओं के लिए माननीय जी. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित शुल्क सौर ऊर्जा
परियोजना के चालू होने की तारीख से प्रभावी
या उपर्युक्त शुल्क, जो भी कम हो।
(जोर दिया गया) "

50. आंध्र प्रदेश लिमिटेड का पारेषण निगम

क), राज्य आयोग ने दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रदाताओं को विशेष रूप से
बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया था। पी. पारेषण निगम। ऊर्जा विकासकर्ताओं को तीसरे
पक्ष को 1 शक्ति की अनुमति नहीं थी। आयोग ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड v की दर को
भी मंजूरी दी।

पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

25/- प्रति इकाई की दर से आपूर्ति के लिए पहले 5 प्रतिशत की वृद्धि दर थी जो आधार वर्ष 1994-1995 थी। नियामक आयोग के आदेश के पारित होने के बाद पक्षों ने पी. पी. ए. में प्रवेश किया। पी. पी. ए. ने वृद्धि दर के साथ प्रति इकाई 2.25/- की दर से शुल्क को मूर्त रूप दिया या प्रतिबिंबित किया। 5 % 1994 को आधार वर्ष के रूप में वार्षिक रूप से 2003-04 तक संशोधित किया जाना है। उसके बाद, खरीद मूल्य राज्य आयोग द्वारा तय किया जाना था। शर्त में यह भी प्रावधान किया गया है कि परियोजना के चालू होने के 10 साल पूरे होने पर खरीद मूल्य की आगे की समीक्षा की जाएगी।

51. ए. पी. पारेषण निगम के कार्य कानून के संचालन द्वारा डिस्कॉम पर हस्तांतरित किए गए थे। इस पृष्ठभूमि में, राज्य आयोग ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा खरीद शुल्कों को संशोधित करने के लिए स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग किया। ए. पी. टी. ई. एल. ने ए. पी. प्रसारण की अपील को खारिज कर दिया

निगम। इस अदालत ने माना कि एक बार समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने और कानून में लागू करने योग्य होने के बाद, इस तरह के लागू करने योग्य दायित्वों को विफल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने बिजली उत्पादक की ओर से दलीलों को भी नकार दिया

कि उन्हें जबरदस्ती या दबाव के अधीन किया गया था। इस संबंध में इस न्यायालय की टिप्पणियां इस संबंध में प्रासंगिक हैं और नीचे उद्धृत की गई हैं:

" 39. [.....] वर्तमान मामले में 20-6-2001 दिनांकित आदेश था

बिना किसी आरक्षण के दलों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया गया। अपनी मर्जी से उचित समय से अधिक समय बीत जाने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर किए जिसमें एक विशिष्ट शर्त थी जिसमें उनके द्वारा तीसरे पक्ष को उत्पादित बिजली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। समझौते में नवीनीकरण का प्रावधान भी था।

ट्रांसको/ए. पी. टी. आर. ए. एन. एस. सी. ओ./बोर्ड को संशोधन करने के लिए सशक्त बनाना शुल्क। इस प्रकार, इन पक्षों द्वारा निष्पादित दस्तावेज और लंबे समय तक ऐसे समझौतों पर कार्य करने का उनका आचरण,

हमारे विचार में, उन्हें अनुबंध में बताए गए अधिकारों और दायित्वों के लिए बाध्य करें। पक्ष शायद ही तथ्यों से इनकार कर सकते हैं क्योंकि वे प्रासंगिक समय पर मौजूद थे, सिर्फ इसलिए कि उन शर्तों का पालन करना अब सुविधाजनक नहीं हो सकता है। किसी अनुबंध की शर्तों को अनुमानों या धारणाओं या दूसरा विचार रखने वाले पक्षों पर बदला/टाला नहीं जा सकता है कि अनुबंध की अवधि बाद के चरण में उनके लिए फायदेमंद नहीं हो सकती है। उन्हें मौजूदा तथ्यों का पालन करना होगा,

जिसकी शुद्धता से वे शायद ही इनकार कर सकते हैं। इस तरह के आचरण को आलोचकों के विरोध से नुकसान होगा। "[2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. अब, हम न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के गुण-दोष या अन्यथा की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि पक्षों द्वारा निष्पादित पी. पी. ए. किसी दबाव का परिणाम थे और इस प्रकार, यह अधिकारियों को शुल्क की समीक्षा करने का अधिकार नहीं देगा और

अन्य दिए गए प्रोत्साहन। पी. पी. ए. पहले निष्पादित किए गए थे और

2001 के 20-6 आदेश के जारी होने के बाद।

अलग-अलग व्यक्तियों ने ऐसे पी. पी. ए. एस. के नियमों और शर्तों के बारे में पूरी जागरूकता में अलग-अलग समय पर अनुबंधों को निष्पादित किया। को।

दबाव या जबरदस्ती के आधार पर किसी अनुबंध को विफल करने के लिए, निश्चित अभिवचन होने चाहिए जिन्हें सामान्य रूप से ठोस और उचित साक्ष्य का नेतृत्व करके प्रमाणित किया जाना चाहिए। हालांकि,

उस मामले में जहां संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे कि

वर्तमान में, कम से कम कुछ दस्तावेजी साक्ष्य या हलफनामा विशेष रूप से इस दबाव की याचिका को उठाते हुए दायर किया जाना चाहिए था।

43. [.....] हमारे सामने के रिकॉर्ड से, कुछ भी नहीं लाया गया था

दबाव की याचिका को बताने और कथित तथ्यों को साबित करने के लिए हमारा नोटिस, जो दबाव का गठन करते हैं, ताकि पी. पी. ए. के प्रभाव को दूषित और/या आंशिक रूप से कम किया जा सके। एक ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण ने बाध्यकारी प्रकृति पर संदेह किया है

अनुबंधों में कहा गया है कि उनमें एकतरफा शर्तें थीं

विनियामक के आदेश और अनुमोदन के आधार पर प्रस्तुत किया गया आयोग, जबकि दूसरी ओर, आदेश के पैरा 53 में,

यह इस धारणा पर आगे बढ़ा कि पी. पी. ए. एस. अंतिम हैं और

बाध्यकारी और अभी भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नियामक आयोग शुल्क में संशोधन नहीं कर सका। यहाँ तक कि क्रम में, नहीं

तथ्यों को इंगित किया गया है जो, की राय में

न्यायाधिकरण, अनुबंध के अर्थ के भीतर गठित दबाव

अनुबंध को रद्द करने योग्य बनाने के लिए कार्य करें।

52. गुजरात में ऊर्जा बनाम। सोलर पावर कंपनी इंडिया प्रा.

इन में यह माना गया था कि: 7) 14 एस. सी. आर 115

6) 5 एस. सी. आर. 990 जरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन का नवीनीकरण करें। एनईआरजीवाई (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" 10. जबकि अधिनियम की धारा 61 के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है शुल्क का निर्धारण, अधिनियम की धारा 62 से संबंधित है -

विभिन्न प्रकार के शुल्क/शुल्क तय किए जाने हैं। धारा 64

शुल्क के निर्धारण के तरीके की गणना करता है आयोग द्वारा किया जाना आवश्यक है। दूसरी ओर,

धारा 86 जो आयोग के कार्यों से संबंधित है

शुल्क के निर्धारण को प्राथमिक में से एक होने के लिए दोहराता है

आयोग के कार्य जिनके निर्धारण में शामिल हैं -

जैसा कि ऊपर देखा गया है, खरीद के संबंध में एक नियामक शक्ति

और उत्पादन करने वाली कंपनियों से बिजली की खरीद

पी. पी. ए. में प्रवेश करना। शुल्क निर्धारण/निर्धारण की शक्ति

निस्संदेह यह वैधानिक है और इसका यही दृष्टिकोण रहा है।

न्यायालय ने ए. पी. ट्रांस्को बनाम के पैरा 36 और 64 में व्यक्त किया। साई।

या खुली बोली के मामले में (धारा 63)। वर्तमान में मामला, निश्चित रूप से, पीपीए में शामिल शुल्क के बीच

उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंसधारी शुल्क है।

राज्य नियामक आयोग द्वारा इसके अभ्यास में तय किया गया

वैधानिक शक्तियाँ। ऐसी स्थिति में पकड़ रखना संभव नहीं है।

सांविधिक शक्तियों का प्रयोग जो एक में शामिल की गई दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता।

**

**

सोलर पावर कंपनी इंडिया प्रा. लि. में यह न्यायालय। लिमिटेड (सुप्रा)

एर ने देखा कि:

35. इस न्यायालय को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए

उपभोक्ता और धारा 61 (डी) के लिए आवश्यक है कि उपयुक्त होने पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जानी चाहिए।

आयोग नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करता है

शुल्क का निर्धारण। धारा 64 के तहत धारा [2023] 7 एस. सी. आर. के साथ पढ़ा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

62, शुल्क का निर्धारण विचार करने के बाद ही किया जाना है।

जनता से प्राप्त सभी सुझाव और आपत्तियाँ। इसलिए, जनता को नोटिस के साथ कानून के तहत निर्धारित सामान्य शुल्क को केवल उसी प्रक्रिया का पालन करके संशोधित किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय के दृष्टिकोण को सतर्क और सावधान रहना चाहिए जब निर्णय का प्रभाव इस पर पड़ता है।

उपभोक्ता।

36. विनियम 85 में समय बढ़ाने का प्रावधान है। यह देखा जा सकता है कि यह केवल दो निर्दिष्ट स्थितियों में उपलब्ध है (i) विनियमों द्वारा निर्धारित समय के विस्तार के लिए, और (ii) कोई भी कार्य करने के लिए आयोग द्वारा अपने आदेश में निर्धारित समय के विस्तार के लिए। नियंत्रण अवधि कुछ नहीं है

आयोग द्वारा व्यवसाय संचालन विनियमों के तहत निर्धारित। नियंत्रण अवधि भी कोई कार्य करने के लिए आयोग का आदेश नहीं है। किसी परियोजना को चालू करना है

पी. पी. ए. के अधीन दायित्व के संदर्भ में निष्पादित किया जाने वाला कार्य और वह निर्माता और खरीदार के बीच है। प्रत्यर्थी 1 और अपीलार्थी। इसलिए, आयोग कोई भी कार्य करने के लिए पी. पी. ए. के तहत निर्धारित समय को नहीं बढ़ा सकता है। विनियमन 85 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समझौते के तहत विचार किया गया। इसलिए, की अंतर्निहित शक्तियों के तहत नियंत्रण अवधि का विस्तार नहीं हो सकता है

आयोग।

37. कानून का सृजन होने के कारण आयोग अपने लिए ऐसी कोई शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता जो अन्यथा उसे प्रदान नहीं की गई हो। दूसरे शब्दों में, अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने की आड़ में, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, आयोग ऐसा नहीं कर सकता है। एक शक्ति का प्रयोग करने का सहारा लें, जिसके लिए प्रक्रिया अन्यथा अधिनियम के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई है।

53. जे. भानुमति द्वारा व्यक्त सहमति वाला विचार, महत्वपूर्ण रूप से आयोजित किया गया

" बिजली खरीद समझौते की पवित्रता

उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच बिजली का उत्पादन और वितरण लाइसेंसधारियों और पी. पी. ए. के नियमों और शर्तों को अलंघनीय नहीं माना जा सकता है।

केवल इसलिए कि पी. पी. ए. में, टैरिफ जरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन का नवीनीकरण करें एनईआरजीवाई (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

शुल्क आदेश, 2010 के अनुसार दर को शामिल किया गया है जो नहीं है

आयोग को अनुबंध की शर्तों को बदलने का अधिकार

उन उपभोक्ताओं का नुकसान जिनके हित में आयोग सुरक्षा के लिए बाध्य है। आपसी सहमति से पक्षों के बीच किए गए पी. पी. ए. की पवित्रता को राज्य आयोग के विस्तार के निर्णय द्वारा उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इसकी समाप्ति तिथि से आगे की पूर्व नियंत्रण अवधि,

उत्पन्न करने वाली कंपनी का लाभ, प्रतिवादी 1 और अपीलार्थी का नुकसान। पी. पी. ए. की शर्तें बाध्यकारी हैं -

दोनों पक्ष समान रूप से।

66. गुजरात में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम। ई. एम. सी. ओ. लिमिटेड, तथ्य समान थे और कानून का सवाल उठाया गया था कि क्या पी. पी. ए. के नियमों और शर्तों को पारित करके, प्रतिवादी पी. पी. ए. की पवित्रता पर हमला कर सकता है। इस न्यायालय ने कहा कि बिजली उत्पादक पी. पी. ए. की शर्तों के खिलाफ नहीं जा सकता है और पी. पी. ए. की शर्तों के अनुसार, यदि पहला प्रतिवादी "नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू करने में सक्षम नहीं है, तो पहला प्रतिवादी केवल कम के लिए हकदार होगा।

शुल्कों को।

54. इसी तरह, बैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम।

आर. के. पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और अन्य 3 2 इस अदालत ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 13. यह तर्क कि 2004 के विनियमों के विनियम 5,3,3,4 के साथ-साथ विद्युत अधिनियम की धारा 61 और 62 के तहत, शुल्क में बदलाव करने की शक्ति आयोग के पास निहित है, उक्त विनियमों में विशेष रूप से प्रदान की गई ऐसी शक्ति केवल निर्धारित करने से पहले ही काम करेगी।

एक बार जब संबंधित बिजली खरीद समझौते अंततः समाप्त हो जाते हैं और बिजली खरीद समझौतों के तहत पक्षों के बीच शर्तों पर सहमति हो जाती है, उसके बाद,

हमारी सुविचारित राय, 2004 का विनियम 5.1

हमारे सामने पक्षकारों के मामले में केवल नियम ही लागू होंगे। नतीजतन, आयोग के लिए अनुमोदित बिजली खरीद समझौते के तहत पक्षों के बीच सहमत शुल्क में बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

55. अधिनियम की धारा 61 शुल्क निर्धारण के लिए आधार बनाती है। दूसरी ओर, धारा 62 विभिन्न के निर्धारण से संबंधित है।

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य शुल्क और शुल्क। धारा 64 आयोग द्वारा शुल्क निर्धारण के तरीके और प्रक्रिया को सूचीबद्ध करती है। धारा 86 आयोग के कार्यों को सूचीबद्ध करती है और शुल्क के निर्धारण को आयोग का एक प्रमुख कार्य बताती है। शुल्क निर्धारण में कोई संदेह नहीं है, विनियामक कार्य की कवायद को समझता है, जिसमें खरीद, सोर्सिंग, जनरेटर से बिजली की खरीद, वितरण और अन्य लाइसेंसधारियों द्वारा और उनकी बिक्री शामिल है। इस भाग में खरीद करने वाली संस्थाओं या लाइसेंसधारियों के साथ पी. पी. ए. (ओं) में प्रवेश करने वाली कंपनियाँ शामिल हैं। शुल्क निर्धारण एक वैधानिक कार्य है। फिर भी, धारा 42 के आधार पर, यह शक्ति की कीमत के खुली पहुंच निर्धारण के अधीन है, और धारा 63 के अधीन है जहाँ भी इसमें खुली बोली शामिल है। इस मामले के तथ्यों में, पी. पी. ए. ने उत्तरदाताओं और गुजरात ऊर्जा के बीच एक शुल्क को शामिल किया

राज्य नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का गठन किया गया अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना। आर. ई. सी. के निर्गम और बिक्री का गठन किया गया

उन सौदे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, दोनों पक्षों के बीच, उनके वाणिज्यिक हित के मूल्यांकन के आधार पर। 56. आर. ई. सी. तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें, डब्ल्यू. पी. डी. (यानी उत्तरदाताओं) को वितरण लाइसेंसधारियों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बिजली बेचनी पड़ती थी, जो डिस्कॉम (जैसे गुजरात ऊर्जा) की औसत बिजली खरीद लागत ('ए. पी. पी. सी.') से अधिक नहीं थी। डब्ल्यूपीडी इसे जारी किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त लाभ के हकदार थे, जिनका एक कीमत पर पावर एक्सचेंज में कारोबार किया जा सकता था। द.

डब्ल्यू. पी. डी. को देय प्रतिफल में पहला, एक पारस्परिक रूप से सहमत बिजली घटक और दूसरा एक्सचेंज में आर. ई. सी. एस. के माध्यम से कारोबार किया जाने वाला एक हरित घटक शामिल था। डब्ल्यूपीडी का विकल्प राज्य आयोग द्वारा निर्धारित तरजीही शुल्क पर लाइसेंसधारियों को बेचना था। बाद की घटना में, डब्ल्यू. पी. डी. हरित घटक के अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं थे, जो कि व्यापार योग्य आर. ई. सी. की बिक्री थी।

आर. ई. सी. तंत्र, इन मामलों में पी. पी. ए. में प्रवेश करते हुए, गुजरात के साथ ऊर्जा। डब्ल्यू. पी. डी. द्वारा किए गए पी. पी. ए. में पूरी अवधि (25 वर्ष) के लिए 2.64/के. डब्ल्यू. एच. के निर्धारित शुल्क का प्रावधान किया गया है, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हुई है (पी. पी. ए. का अनुच्छेद 5.2)। डब्ल्यू. पी. डी. आर. ई. सी. के हकदार थे और सत्ता में व्यापार कर रहे थे।

विनिमय, अतिरिक्त मौद्रिक लाभ प्राप्त करना: जो, प्रासंगिक अवधि में 1.5/kWh (पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने के समय न्यूनतम मूल्य) था। द.

आर. ई. सी. तंत्र का विकल्प नहीं चुनने वाले डब्ल्यू. पी. डी. के लिए राज्य आयोग द्वारा निर्धारित तरजीही शुल्क ₹356/के. डब्ल्यू. एच. था। डब्ल्यू. पी. डी. किसी भी अतिरिक्त आर. ई. सी. लाभ के हकदार नहीं थे, अगर उन्होंने तरजीही शुल्क मार्ग अपनाया होता।

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

57. उत्तरदाताओं ने राज्य आयोग और ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष सफलतापूर्वक शिकायत की कि पी. पी. ए., जिसे उन्होंने गुजरात ऊर्जा के साथ किया था, जिसके तहत शुल्क ₹2.64/के. डब्ल्यू. एच. (उनके द्वारा बेचे गए आर. ई. सी. की कीमत के साथ) तय किया गया था, लंबे समय में 3.56/के. डब्ल्यू. एच. से कम फायदेमंद था। सुनवाई के दौरान, यह आग्रह किया गया कि एक्सचेंज में आर. ई. सी. की लागत कम हो रही है, जबकि तरजीही शुल्क बढ़ गए थे। इस पहलू पर, आर. ई. सी. विनियम 2010 का विनियम 9 बिजली विनियम में आर. ई. सी. के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र निर्धारित करता है। आर. ई. सी. विनियम 2010 के विनियम 9 (1) का प्रावधान केंद्रीय आयोग के साथ परामर्श करके केंद्रीय आयोग को सशक्त बनाता है।

एजेंसी और नियामकों का मंच, सौर और गैर-सौर प्रमाणपत्रों के लिए अलग से न्यूनतम मूल्य और सहनशीलता मूल्य प्रदान करेंगे। यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनहित में नियामक हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है: यदि मूल्य एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है, तो उत्पादकों के हितों का ध्यान रखने के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाना था-जैसे कि उत्तरदाताओं; यदि मूल्य बहुत अधिक हो जाता है, तो उपभोक्ताओं और वितरकों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक सहनशीलता मूल्य तय किया जा सकता है। आर. ई. सी. विनियम 2010 के विनियम 9 (2) के अनुसार, केंद्रीय आयोग को विभिन्न कारकों जैसे कि (ए) देश के विभिन्न राज्यों में सौर और गैर-सौर श्रेणी के तहत आने वाली विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उत्पादन की लागत में भिन्नता; (बी) देश के विभिन्न राज्यों में खरीद की कुल लागत में भिन्नता; (सी) गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अपेक्षित बिजली उत्पादन [जिसमें (आई) तरजीही शुल्क के तहत अपेक्षित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (आई) प्रमाण पत्रों के तंत्र के तहत अपेक्षित नवीकरणीय ऊर्जा] (डी) विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित नवीकरणीय खरीद दायित्व लक्ष्यों द्वारा आधार और सहनशीलता मूल्य निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया जाना था। आर. ई. सी. विनियमों के विनियम 5 (1) के स्पष्टीकरण के आधार पर, भारत औसत एकत्रित मूल्य

जिसे वितरण लाइसेंसधारी ने बिजली खरीदी है जिसमें पिछले वर्ष में सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से दीर्घकालिक और अल्पकालिक स्व-उत्पादन की लागत, यदि कोई हो, शामिल है, लेकिन अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित लागत को छोड़कर, जैसा भी मामला हो। अ.

महत्वपूर्ण कारक जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि प्रतिवादी के सभी डब्ल्यू. पी. डी. 2010 के राज्य आयोग के शुल्क आदेश के आधार पर आर. ई. सी. विनियमों के तहत पंजीकृत थे। यह निर्विवाद है कि आर. ई. सी. विनियम 2010 के तहत पंजीकरण करने के लिए, एक इकाई (जैसे डब्ल्यू. पी. डी.) को (ए) राज्य एजेंसी के साथ मान्यता प्राप्त होना चाहिए [(आर. ई. सी. विनियमों के विनियम 2 (एन) द्वारा परिभाषित एक एजेंसी के रूप में "राज्य आयोग द्वारा नामित"।

मान्यता के लिए एजेंसी के रूप में कार्य करना और [2023] 7 एस. सी. आर. की सिफारिश करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजीकरण के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं) और ऐसी इकाई जिसके पास ऐसी क्षमता के लिए कोई बिजली खरीद समझौता नहीं है।

उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिमन्य शुल्क पर बिजली बेचने के लिए उत्पादन]। 58. इसके अलावा, राज्य आयोग ने तरजीही शुल्क का निर्धारण करते हुए अपने टैरिफ आदेश, दिनांक 30.01.2010 (जो 10.08.2009 से शुरू होने वाली नियंत्रण अवधि के साथ तीन साल के लिए चालू था) में कहा था कि यह 25 वर्षों के लिए लागू होगा:

" इसलिए आयोग पवन ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के लिए शुल्क निर्धारित करता है। 3. 56 (स्थिर) इसके 25 वर्षों के पूरे परियोजना जीवन के लिए अर्थात् पहले वर्ष से लेकर 25वें वर्ष तक। यह शुल्क वितरण लाइसेंसधारियों/अन्य लोगों द्वारा पवन ऊर्जा की खरीद पर लागू होगा।

समय-समय पर आयोग द्वारा विनियमन में निर्दिष्ट अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों का पालन करने के लिए संस्थाएं। यह शुल्क पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर लागू होता है।

कौन से नए पवन ऊर्जा संयंत्रों को चालू करते हैं और

11 अगस्त, 2009 से उपकरण।

59. वर्तमान मामले में, पक्षों द्वारा पी. पी. ए. में प्रवेश किया गया था। 29.03.2102 पर, के प्रशुल्क आदेश में निर्धारित नियंत्रण अवधि के भीतर

2010. आर. ई. सी. विनियम 2010 में परिवर्तन, जिसके तहत विनियम 5 के स्पष्टीकरण में संशोधन किया गया था, के परिणामस्वरूप परिवर्तन हुआ। पहले से मौजूद खंड कि बिजली "बिजली खरीद की एकत्रित लागत से अधिक नहीं होगी" को "बिजली खरीद की एकत्रित लागत पर" में बदल दिया गया था। यह परिवर्तन, दूसरे संशोधन (आर. ई. सी. विनियमों में) के माध्यम से किया गया था, जिसे 10.07.2013 पर किया गया था। यह रिकॉर्ड की बात है कि 29.03.2102 और 10.07.2013 के बीच की अवधि के लिए-और वास्तव में, दूसरे संशोधन के बाद, पीपीए के तहत पक्षों द्वारा सहमत मूल्य निर्धारण तंत्र में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं किया गया था। यह 10.12.2013 पर था कि प्रतिवादी WPD ने राज्य आयोग से संपर्क किया

शुल्क का निर्धारण। स्पष्ट रूप से, यह दूसरे संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने का एक अवसरवादी प्रयास था, और इसे एक मौजूदा अनुबंध पर लागू करने का प्रयास था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन कारणों को देखते हुए, यह माना जाता है कि ए. पी. टी. ई. एल. और राज्य आयोग के तर्क को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

द्वितीय संशोधन का पूर्व-विद्यमान पर लागू होना

अनुबंध-सामान्य कानून गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन का नवीनीकरण करें

ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

60. बिजली खरीद समझौते अनिवार्य रूप से वैधानिक नहीं हैं।

61. द्वितीय संशोधन के विनियम 1 (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि संशोधन उनकी तारीख से लागू होने वाले थे। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन, जो 10 जुलाई, 2013 को है। इसके अलावा, दूसरे संशोधन के साथ कारणों का विवरण,

स्पष्ट किया कि मौजूदा पी. पी. ए. प्रभावित नहीं हुए थे:

" कुछ हितधारकों ने स्पष्ट करने का सुझाव दिया है कि

क्या एपीपीसी से कम कीमत पर निष्पादित पी. पी. ए. आर. ई. सी. तंत्र के तहत अयोग्य हो जाएंगे। यह महसूस किया जाता है कि ए. पी. पी. सी. से कम या अधिक बिजली घटक के लिए शुल्क से आर. ई. जनरेटर को नुकसान या लाभ हो सकता है। आयोग यह स्पष्ट करना चाहेगा कि एपीपीसी से कम शुल्क पर पीपीए निष्पादित करने वाली परियोजनाओं पर रोक लगाने का इरादा नहीं है। यह संशोधन संभावित रूप से लागू होगा और इस तरह एपीपीसी से कम पर पहले से ही निष्पादित पी. पी. ए. एस. को प्रभावित नहीं करेगा।

62. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पी. टी. सी. इंडिया (ऊपर) में संकेत दिया था कि राज्य आयोगों के पास मौजूदा अनुबंधों, विशेष रूप से पी. पी. ए. एस. को बदलने की शक्ति है:

" 40. [.....] विनियमन एक ऐसी कवायद है जो विनियम बनाने से अलग है। हालांकि, धारा 178 के तहत विनियमन बनाना केंद्र के लिए पूर्व शर्त नहीं है। आयोग धारा 79 (1) के तहत कोई भी कदम/उपाय कर रहा है। जैसा कि कहा गया है, यदि कोई विनियमन है, तो [2023] 7 एस. सी. आर. के तहत उपाय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 79 (1) को धारा 178 के तहत ऐसे विनियमन के अनुरूप होना चाहिए। यह सिद्धांत इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से निकलता है, जिन पर हमने आगे चर्चा की है। के लिए

उदाहरण के लिए, धारा 79 (1) (जी) के तहत, केंद्रीय आयोग को 2003 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए शुल्क लगाने की आवश्यकता है। धारा 178 के तहत विनियमन के अभाव में भी नियामक शुल्क लगाने का आदेश पारित किया जा सकता है। यदि शुल्क अनुचित है, तो यह धारा 111 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय हो सकता है क्योंकि शुल्क एक आदेश/निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इसके तहत एक विनियमन बनाना धारा 178 आदेश पारित करने की पूर्व शर्त नहीं है।

धारा 79 (1) (छ) के तहत नियामक शुल्क लगाना। तथापि, यदि उस संबंध में धारा 178 के तहत कोई विनियम है तो धारा 79 (1) (छ) के तहत शुल्क लगाने का आदेश ऐसे विनियमन के अनुरूप होना चाहिए।

*

**

40. [.....] एक पर धारा 178 के तहत विनियमन बनाने की शक्ति के बीच द्विभाजन को ध्यान में रखना चाहिए।

धारा 79 (1) में हाथ और विभिन्न गणना किए गए क्षेत्र जिनमें केंद्रीय आयोग को ऐसा करने के लिए अनिवार्य किया गया है

2003 के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो उपाय उचित समझते हैं।

इस परीक्षण को वर्तमान विवाद पर लागू करते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 79 (1) में उल्लिखित ऐसा एक क्षेत्र व्यापार मार्जिन के निर्धारण को संदर्भित करता है। इस संबंध में विनियमन बनाना केंद्रीय आयोग की पूर्व शर्त नहीं है।

धारा के तहत व्यापार मार्जिन तय करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना 79 (1) (जे) तथापि, यदि केन्द्रीय आयोग एक उपयुक्त मामले में, जैसा कि यहाँ मामला है, एक सीमा निर्धारित करने वाला विनियमन बनाता है।

धारा 178 के तहत व्यापार मार्जिन पर फिर जो कुछ भी हो

धारा 79 (1) (जे) के तहत केंद्रीय आयोग द्वारा किए गए उपाय धारा 178 के अनुरूप होने चाहिए। एक अवश्य।

इस कारण को समझें कि एक विनियमन क्यों बनाया गया है

धारा 178 के तहत व्यापार मार्जिन को सीमित करने का मामला अधिनियम से। एक व्यापारिक मार्जिन तय करने के बजाय (जिसमें शामिल हैं)

कैपिंग) मामले-दर-मामले के आधार पर, केंद्रीय आयोग ने एक विनियमन बनाना उचित समझा जिसमें एक सामान्य नियम है।

संपूर्ण व्यापारिक गतिविधि के लिए अनुप्रयोग जो किया गया है 2003 के अधिनियम के तहत पहली बार मान्यता प्राप्त।

इसके अलावा, यह जे. ए. आर. ए. टी. यू. आर. जे. विकास निगम लिमिटेड वी. पवन का नवीनीकरण करें एनईआरजीवाई (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसके तहत एक विनियमन बनाना

धारा 178 आवश्यक हो गई क्योंकि एक विनियमन बनाया गया था

धारा 178 के तहत हस्तक्षेप और ओवरराइडिंग का प्रभाव पड़ता है।

विनियमित के बीच मौजूदा संविदात्मक संबंध

इकाइयाँ। धारा 178 के तहत एक विनियमन की प्रकृति है

अधीनस्थ विधान। इस तरह के अधीनस्थ कानून भी कर सकते हैं

बिजली खरीद सहित मौजूदा अनुबंधों को हटा दें। जिन समझौतों को नियमों के साथ जोड़ा जाना है

धारा 178 के तहत और जो नहीं किया जा सकता था

केंद्रीय आयोग के एक आदेश के तहत बोर्ड भर में धारा 79 (1) (जे)।

*

*

ए-अधिनियम के तहत एक विनियमन के रूप में, किसी को परीक्षण लागू करने की आवश्यकता है सामान्य अनुप्रयोग। विवादित 2006 के निर्माण पर

विनियम, यहाँ तक कि मौजूदा बिजली खरीद समझौते भी

(पी. पी. ए.) को संशोधित और उक्त के साथ संरेखित किया जाना था

नियम। दूसरे शब्दों में, विवादित विनियम बनाते हैं

मौजूदा अनुबंधों में भी प्रवेश। यह स्वयं इंगित करता है

धारा के तहत सी. ई. आर. सी. को प्रदत्त शक्ति की चौड़ाई

178 2003 के अधिनियम से। उसके बाद अस्तित्व में आने वाले सभी अनुबंध

विवादित 2006 विनियमों के निर्माण को भी ध्यान में रखना होगा

व्यापार मार्जिन की सीमा में। यह स्वयं इंगित करता है कि

विवादित विनियम अधीनस्थ प्रकृति के होते हैं।

इस तरह का नियामक हस्तक्षेप
कानून।

में

बोर्ड भर में मौजूदा अनुबंध किए जा सकते थे

केवल धारा 178 के तहत विनियम बनाकर और नहीं

2003 के अधिनियम की धारा 79 (1) (जे) के तहत एक आदेश को दरकिनार करना।

इसलिए, हमारे विचार में, यदि हम उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हैं ध्यान रहे, यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 111 में "आदेश" शब्द है।

2003 के अधिनियम में विवादित 2006 के विनियम शामिल नहीं हो सकते हैं।

2003 के अधिनियम की धारा 178 के तहत बनाया गया।

63. हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इसके तहत बनाए गए नियम

सी. टी. को मौजूदा अनुबंधों पर लागू किया जा सकता है, जो स्पष्ट है

पी. टी. सी. इंडिया (ऊपर) यह है कि उस मामले में, व्यापार की प्रयोज्यताविनियमों में जो पहली बार, मजबूर व्यक्तियों को लगे हुए थे

अधिनियम की धारा 2 (17) के अनुसार, [2023] 7 एस. सी. आर. में दर्शाई गई सीमा के भीतर पंजीकरण, एन. लाइसेंस और संचालन के लिए बिजली का उपयोग।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम। इन प्रावधानों ने एक नए शासन की शुरुआत की, जो एक ऐसे क्षेत्र या गतिविधि को विनियमित करता है जो अब तक अनियमित था। इसके दायरे में काम करने वाले सभी लोगों के लिए आवेदन के लिए सामान्य मानकों को निर्धारित करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सार्वभौमिक हैं और एक संहिता का गठन करते हैं। इसलिए, पी. टी. सी. इंडिया (ऊपर) में टिप्पणियों को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सामान्य अनुप्रयोग के नियम होने के नाते, वाणिज्यिक गतिविधि की एक श्रृंखला से निपटने के लिए, मौजूदा अनुबंधों का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था, जो अलग-अलग साइलो के माध्यम से अलग-अलग काम कर रहे थे।

फ्रेमवर्क। हालाँकि, वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. को पक्षों द्वारा उचित बातचीत के बाद और मौजूदा नियमों के ढाँचे के भीतर समान सौदेबाजी की शक्ति के प्रयोग में प्रवेश किया गया था: केंद्र और राज्य दोनों। इसलिए, जब तक कि कोई बाद का संशोधन स्पष्ट रूप से मौजूदा अनुबंधों को ओवरराइड नहीं करता है, ऐसे समझौतों की शर्तें पक्षों को बाध्य करती हैं।

64. कानून या विनियमों में संशोधन, जब तक कि स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी न हो, हमेशा संभावित होते हैं, यह एक तय प्रस्ताव है। में। पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर (पी) लिमिटेड v. असम राज्य विद्युत बोर्ड और Ors.³³ 33, स्थिति को इस तरह से व्यक्त किया गया था:

" 39. [.....] इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि कोई भी मूल कानून संभावित रूप से तब तक काम करेगा जब तक कि कानून की भाषा में पूर्वव्यापी संचालन स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता है। केवल एक प्रक्रियात्मक या घोषणात्मक कानून पूर्वव्यापी रूप से काम करता है क्योंकि प्रक्रिया में कोई निहित अधिकार नहीं है।

40. अधिनियम के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के किसी भी स्पष्ट विधायी इरादे के अभाव में, और के आधार पर

तथ्य यह है कि अधिनियम खरीदार के खिलाफ उच्च ब्याज दर का एक नया दायित्व पैदा करता है, अधिनियम का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि

पूर्वव्यापी प्रभाव। चूंकि अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि आपूर्तिकर्ता को अधिनियम के संदर्भ में उच्च ब्याज दर का दावा करने का उपार्जित अधिकार है, इसलिए इसे केवल अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख यानी 23 के बाद बिक्री समझौतों के लिए उपार्जित कहा जा सकता है।

9-1992 और किसी भी समय पहले नहीं।

65. आयकर आयुक्त बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) Ltd.³⁴ में, इस न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा कि:

" 31. किसी कानून की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले विभिन्न नियमों में से एक स्थापित नियम यह है कि जब तक कि इसके विपरीत न हो।

33 (2012) 6 एस. सी. आर 905

34 (2014) 12 एस. सी. आर. 1037 जरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन का नवीनीकरण करेंएनईआरजीवाई (राजकोट) पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इरादा प्रकट होता है, एक कानून को पूर्वव्यापी संचालन का इरादा नहीं माना जाता है। इस नियम के पीछे का विचार यह है कि एक वर्तमान कानून को वर्तमान गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए। आज पारित कानून अतीत की घटनाओं पर लागू नहीं हो सकता है। अगर हम आज कुछ करते हैं, तो हम उसे आज और लागू कानून को ध्यान में रखते हुए करते हैं, न कि कल के पिछड़े समायोजन को ध्यान में रखते हुए। कानून की प्रकृति में हमारा विश्वास इस आधार पर स्थापित है कि प्रत्येक मनुष्य को मौजूदा कानून पर भरोसा करके अपने मामलों को व्यवस्थित करने का अधिकार है और यह नहीं देखना चाहिए कि उसकी योजनाएं पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित हुई हैं। कानून के इस सिद्धांत को लेक्स प्रॉस्पिसिट नॉन रेस्पिसिट के रूप में जाना जाता है: कानून आगे देखता है न कि पीछे। जैसा कि फिलिप्स वी में देखा गया था। आयर [फिलिप्स बनाम। आयर, (1870) एल. आर. 6 क्यू बी. 1], एक पूर्वव्यापी कानून, उस सामान्य सिद्धांत के विपरीत है जिसके द्वारा पहली बार मानव जाति के आचरण को विनियमित किया जाना है।

भविष्य के कार्यों से अतीत का चरित्र नहीं बदलना चाहिए।

तत्कालीन मौजूदा लोगों के विश्वास पर किए गए लेनदेन

कानून।

फॉस्फेट v. यामाशिता-शिन्निहोन स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड, (1994) 1 सभी ई. आर. 20 (एच. एल.)] इस प्रकार, ऐसे विधान जो अर्जित अधिकारों को संशोधित करते हैं या जो दायित्वों को लागू करते हैं या नए कर्तव्यों को लागू करते हैं या संलग्न एक नई विकलांगता को संभावित माना जाना चाहिए जब तक कि

विधायी इरादा स्पष्ट रूप से अधिनियम को एक देना है

पूर्वव्यापी प्रभाव; जब तक कि कानून किसी पूर्व कानून में स्पष्ट चूक प्रदान करने या पूर्व कानून की व्याख्या करने के उद्देश्य से न हो। हमें इस विषय पर उपलब्ध केस लॉ के दृष्टिकोण पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपरोक्त कानूनी स्थिति विभिन्न निर्णयों से स्पष्ट रूप से उभरती है और यह

पक्षकारसभक वकील द्वारा कानूनी स्थितिकें स्वीकार कयल गेल छल। किसी भी मामले में, हम इस उक्ति वाले कुछ निर्णयों का उल्लेख कुछ समय बाद करेंगे।

इस प्रस्ताव को फिर से समझाया गया और संघ में लागू किया गया: वी. इंडसइंड बैंक लिमिटेड 35.

66. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि समझौते,

वर्तमान मामले में पी. पी. ए. के रूप में, स्वेच्छा से किया गया

6) 11 एस. सी. आर. 700 [2023] 7 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्ष, दूसरे संशोधन से पहले, इसकी शर्तों से प्रभावित नहीं थे। विवादित क्रम में इसके विपरीत निष्कर्षों को अलग रखा जाता है।

क्या उत्तरदाताओं को पी. पी. ए. एस. में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था

67. राज्य आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि पी. पी. ए. भी आर. ई. सी. विनियमों के पूर्व-संशोधित नियम 5 के गैर-अनुरूप होने की सीमा तक अप्रवर्तनीय थे, क्योंकि अनुबंध असमान सौदेबाजी शक्ति वाले पक्षों द्वारा किए गए थे। यह पहलू था

ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा नोट किया गया, जो निम्नानुसार था:

" 9.19 [.....] राज्य आयोग ने दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के उचित विश्लेषण के बाद विवादित आदेश में अपने निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि शुल्क और अन्य संबंधित शर्तों से संबंधित पी. पी. ए. में परिकल्पित शर्तें अपीलार्थी के पक्ष में एकतरफा प्रतीत होती हैं और

तदनुसार जबरदस्ती या दबाव के मामले का निष्कर्ष निकाला और

दलों के बीच असमान सौदेबाजी की शक्ति

अन्याय और विकृति से भरे समझौते को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि राज्य आयोग ने कानून के अनुसार इस मुद्दे का सही विश्लेषण किया है और ठोस तर्क देते हुए आदेश पारित किया है। इस प्रकार, हम अपने लिए कोई भौतिक मामला या आधार नहीं पाते हैं

मामले में हस्तक्षेप।

10. हमारे निष्कर्षों का सारांश:

सावधानीपूर्वक विचार और आलोचना को ध्यान में रखते हुए

अपीलार्थियों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील के तथ्यों और प्रस्तुतियों का विश्लेषण, हम मानते हैं कि राज्य आयोग के निष्कर्ष न्यायसंगत और सही हैं

कानून के अनुसार "।

68. आंध्र प्रदेश लिमिटेड का पारेषण निगम

(ऊपर), इस न्यायालय ने जबरदस्ती के विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 42. [.....] दबाव या जबरदस्ती के आधार पर किसी अनुबंध को विफल करने के लिए, निश्चित अभिवचन होने चाहिए जिन्हें सामान्य रूप से ठोस और उचित साक्ष्य का नेतृत्व करके प्रमाणित किया जाना चाहिए। हालांकि, उस मामले में जहां संक्षिप्त प्रक्रिया है

वर्तमान की तरह अपनाया गया, कम से कम कुछ दस्तावेजी साक्ष्य या हलफनामा दायर किया जाना चाहिए था

विशेष रूप से दबाव का अनुरोध। [.....] "

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड v. पवन ऊर्जा (राजकोट) पी. वी. टी. का नवीनीकरण करें। लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

69. शांति बुधिया में वेस्ता पटेल और अन्य। वी. निर्मला जयप्रकाश तिवारी और Ors.36, इस अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी या जबरदस्ती स्थापित करने के लिए, "(ए) जबरदस्ती या धोखाधड़ी का एक स्पष्ट आरोप होना चाहिए, और (बी) ऐसे आरोपों के समर्थन में सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और उच्च स्तर की सटीकता के साथ रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि जबरदस्ती या धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, तो इसे पूरे विवरण के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए।" न्यायालय ने बिशुदेव नारायण बनाम में प्रतिपादित सिद्धांत का हवाला दिया था और उसे लागू किया था। सेओगेनी राय 3 जहाँ यह माना गया था कि:

[.....] अब अगर कोई एक नियम है जो किसी भी अन्य की तुलना में बेहतर स्थापित है, तो वह यह है कि धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के मामलों में, इसका अनुरोध करने वाले पक्षों को पूरी तरह से निर्धारित करना चाहिए।

विवरण और मामले का निर्णय केवल निर्धारित विवरणों पर ही किया जा सकता है। सबूत में उनसे कोई विचलन नहीं हो सकता है। सामान्य आरोप धोखाधड़ी के प्रमाण के लिए भी अपर्याप्त हैं, जिस पर किसी भी अदालत को ध्यान देना चाहिए, भले ही वे जिस भाषा में बोले गए हों, वह कितनी भी मजबूत हो, और यही अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती पर भी लागू होता है।

[सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 6 नियम 4 देखें।] "

70. न्यू इंडियन एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 3 8 इस न्यायालय ने उन मामलों में आवश्यक अभिवचनों और साक्ष्य के मानकों पर विचार किया, जहां जबरदस्ती या दबाव का आरोप लगाया गया है:

" 8. इसलिए यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव का एक गंजा अनुरोध पर्याप्त नहीं है और वह पक्ष जो एक याचिका स्थापित करता है, मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के समक्ष सामग्री प्रस्तुत करके इसे प्रथम दृष्टया स्थापित करना चाहिए।

71. वर्तमान मामले में, इस हितकारी नियम को राज्य आयोग द्वारा हवा में फेंक दिया गया था। इस अदालत की राय में, एपीटीईएल, सबसे अधिक पक्षकारों द्वारा पी. पी. ए. में प्रवेश करने के संबंध में बल प्रयोग पर राज्य आयोग के निष्कर्षों पर घुड़सवार शैली, वस्तुतः रबर ने मुहर लगा दी। गुजरात ऊर्जा के खिलाफ कथित जबरदस्ती के आरोप के अलावा कोई सबूत नहीं था, न ही दलीलों की कोई विशिष्टता थी। यह है।

इस तरह के आरोप पर कैसे विचार किया जा सकता था, यह समझ से बाहर है।

और एक निष्कर्ष के रूप में शामिल किया गया, यह देखते हुए कि उत्तरदाता स्थापित कंपनियां हैं, जो बातचीत में प्रवेश करती हैं और अनुबंधों को अंतिम रूप देने पर कानूनी सलाहकारों सहित विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त करती हैं। निष्कर्ष

36 (2010) 4 एस. सी. आर 958 37 (1951) 1 एससीआर 548

38 2014 (12) एससीआर 360 [2023]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, जबरदस्ती के संबंध में पूरी तरह से असमर्थनीय हैं। यह राय कि ए. पी. टी. ई. एल. के आकस्मिक दृष्टिकोण को, इस तरह के निष्कर्षों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक न्यायाधिकरण, जो अनुबंधों और सौदेबाजी से निपटता है, जो समान सौदेबाजी की शक्ति वाले पक्षकार हैं, एपीटीईएल से उचित अभिवचन या साक्ष्य की जांच के बिना जबरदस्ती या धोखाधड़ी के निष्कर्ष देने की उम्मीद नहीं की जाती है। जबरदस्ती के निष्कर्षों को अलग रखा जाता है।

निष्कर्ष

कायम रहा। तदनुसार उन्हें अलग रखा जाता है। अपील अपीलार्थियों को देय लागतों से संबंधित है। दिव्या पांडे

एपी

(शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)

